सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक

जमशेदपुर, नवम्बर 30—दिसम्बर 2, 1983

अध्यक्षीय भाषण

—बी. टी. रणदिवे

साथियों,

सीटू के पांचवे सम्मेलन के बाद कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है. वैसे तो यह बैठक और पहले होनी चाहिए थी परन्तु एक के बाद एक घटना क्रम होने के कारण हम समय पर नहीं कर पाए.

यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि मौत हमारे बीच से हमारी कीमती कामरेडों को छिन रही है जिससे हम और अधिक अनाश्रित तथा असहाय महसूस कर रहे हैं.

मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय कमेटी के सदस्य महान क्रांतिकारी नेता का. एम आर वैंकट रमण को हम अपनी भाव भिनि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. हम यह आशा करते हैं कि उनकी याद हमें प्रेरणा दिलाती रहेगी.

उन सारे मजदूरों और नेताओं को भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों, खासकर गुजरात (कादला), बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान (कोटा) आदि में सरकार तथा असंगठित गुंडा गिरोहों के बर्बर दमन के शिकार हुए. हमें खेद है कि कभी-कभी इस तरह के हमले प्रतिस्पर्द्धी ट्रेड यूनियन संगठनों के सदस्यों तथा समर्थकों के द्वारा किए जाते हैं और इस प्रकार मालिकान और सरकार के हाथ मजबूत किए जाते हैं. मोदीनगर, उत्तर प्रदेश में, सीटू कार्यकर्त्ताओं की निर्मम हत्याओं की यही दुखद कथा है. हम उन मजदूरों का आदर के साथ स्मरण करते हैं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर भी सीटू के झंडे को बुलंद रखा था. इन शहीदों की यादगार ही फैक्टरियों में काम कर रहे हमारे मजदूरों को तथा सीटू को, इस्पात बनाती है और आगे बढ़ने का हौसला देती है. हम अपने उन साथियों का भी गर्म जोशी से अभिनंदन करते हैं जिन्हें नाजायज रूप से जेलों में भर दिया गया. उन्हें रिहा किए जाने की मांग करने के लिए हम अपने सभी संगठनों से आह्वान करते हैं.

साथियों, इसी तरह की एक और दुखद कहानी उड़ीसा, के राउरकेला के निकट कलता में दुहराई गई है. खदान तथा इस्पात मजदूरों के बीच सीटू के बढ़ते प्रभावों को रोक न पाने के कारण प्रतिस्पर्द्धी यूनियन के सदस्यों ने हमारे नेता अनन्त राउत पर कायरता पूर्ण हमले की योजना बनाई. इन गुंडों ने अनंत राउत के घर में घुसकर उनके परिवार वालों पर कातिलाना हमला किया तथा उनके पांच वर्षीय पुत्र की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी. वहशी दरिंदों के हत्यारे मुहिम ने जिस बर्बरता से एक मासूम की हत्या की उसे भर्त्सना करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं. जिन्होंने यह किया और जिन लोगों की उकसावे में यह नृशंस हत्याकांड किया गया, दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. हम का. राउत एवं उनके परिवार के प्रति अपना सहानुभूति का इजहार करते हैं तथा जिस असाधारण बहादुरी से उनके परिवार ने इस त्रासदी का सामना किया उसका हम अभिनंदन करते हैं. इस तरह का साहस ही हैं जो हमारे मजदूरों और कार्यकर्त्ताओं को इस्पात बनाता है. यही साहस है जो सीटू के नाम को, मजदर वर्ग के हित के लिए त्याग तथा भारी आपदाओं के बीच भी क्रांतिकारी दृढ़ता को पर्यायवाची बना देती है.

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

साथियों, हमारे पांचवे सम्मेलन में युद्ध के बढ़ते हुए खतरे तथा निरंतर बिगड़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को नोट किया था. पिछले छ: महीनों में स्थिति और भी खतरनाक हो गई है एवं युद्ध का खतरा और भी वास्तविक हो गया है. सोवियत संघ को ध्वंस करने के उद्देश्य से योरोप में नई मिसाइलें लगाने की अपनी मुहिम के जरिए अमरीकी साम्राज्यवादी तथा उनके सहयोगी, दुनिया को नाभिकीय विनाश की ओर धकेल रहे हैं. इन तमाम अस्त्रों से सुसज्जित होकर वार्त्ताओं के आर में अमरीकी साम्राज्यवाद, समाजवादी सोवियत संघ पर सैनिक बढ़त हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है और इसलिए ब्रिटेन तथा फ्रांस की नाभिकीय शक्ति, जो कि नाटो गठबंधन नाभिकीय शक्ति की 20 फीसदी है, को अमल में लाने से इंकार कर रही है.

सोवियत संघ ने इस खतरनाक स्थिति को टालने के लिए तथा दुनिया के लोगों को युद्ध के विनाश से बचाने के लिए अनेक ठोस प्रस्तावों को सामने रखा. इसने एक तरफा रूप से नाभिकीय अस्त्रों का प्रथम प्रहार न करने की घोषणा की है. दुनिया के लोगों ने अमरीका तथा योरोप के सरकारों से भी इसी तरह के ऐलान की उम्मीद की थी.

सोवियत विदेश मंत्री आंद्रेइ ग्रोमिको ने पिछले 5 अक्तूबर को दो प्रस्ताव पेश किए — एक में नाभिकीय युद्ध की भर्त्सना

की गई और दूसरे में नाभिकीय अस्त्रों पर जाम की सिफारिश की गई. इन दोनों प्रस्तावों को राष्ट्र संघ के 38वां अधिवेशन के कार्य क्रम में शामिल किए जाने की मांग की. पहला प्रस्ताव में कहा गया "साधारण परिषद समूचे मानव समाज के विनाशकारी नाभिकीय युद्ध के बढ़ते खतरे के प्रति अपनी गम्भीर चिंता व्यक्त करता है और विश्व के तमाम देशों तथा लोगों से इसे समाप्त करने के लिए ध्यान आकर्षण करता है — क्योंकि एक बार शुरू हो जाने पर इस नाभिकीय युद्ध के विनाश को सिमीत नहीं किया जा सकता, इस में कोई विजयी नहीं हो सकता —

(1) दृढ़ता पूर्वक, बिना शर्त के तथा सदा के लिए नाभिकीय युद्ध की भर्त्सना करता है क्योंकि यह मानव विवेक विरोधी है और इस युद्ध को मानवजाति के खिलाफ तमाम मानव अधिकारों के खिलाफ, सबसे घिनौना अपराध समझता है.

(2) नाभिकीय बढ़त तथा उसके पश्चात् नाभिकीय युद्ध छेड़ने की एवं प्रथम प्रहार के औचित्य को स्थापित करने के लिए राजनैतिक तथा सैनिक योजनाओं की रचना, प्रतिज्ञा प्रसार तथा प्रचार को एक अपराध पूर्ण कार्य घोषित करता है.

दूसरे प्रस्ताव में नाभिकीय अस्त्र धारी सभी राष्ट्रों से, नाभिकीय अस्त्रों पर जाम लगाने तथा नए नाभिकीय अस्त्रों का तैनात बंद करने के लिए अनुरोध किया गया है.

सोवियत संघ तथा अमरीका, को जिसके पास सबसे अधिक संख्या में नाभिकीय अस्त्र मौजूद है, यह आह्वान देती है कि सबसे पहले अस्त्रागारों पर जाम लगाए साथ ही साथ उदारता पूर्वक नाभिकीय अस्त्रों पर जाम लगाकर अन्य नाभिकीय देशों के सामने एक मिशाल रखें जिसे देखकर अन्य देश भी जल्द से जल्द अपने नाभिकीय अस्त्रों पर जाम लगा सके.

साम्राज्यवादियों ने, दुनिया को नाभिकीय विनाश से बचाने का, राष्ट्रों का राष्ट्रों के बीच अविश्वास के वातावरण को हटाने के लिए किए गये इन प्रस्तावों को अमल में नहीं लाया.

इसके अलावा, सोवियत संघ ने जेनिवा में वार्त्ताओं द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए धीरे-धीरे अस्त्रों के परिसिमन के लिए कई ठोस प्रस्ताव भी दिये. इसने योरोप में मिसाइलें घटाये जाने का भी प्रस्ताव दिया बशर्ते कि विपक्ष भी समान रूप से कटौती में सहमत रहे. सोवियत संघ ने यह भी कहा कि मौजूदा अस्त्रों को पूरी तरह नष्ट किए जाने तथा निरस्त्रीकरण के सवालों पर दोनों पक्षों में सहमति होने तक, देशों की सुरक्षा के सवालों पर वर्तमान सैनिक संतुलन को बरकरार रखना और उसे असंतुलित न करना ही सबसे अच्छी बात होगी. क्रूइस तथा पर्शिंग जैसे नये अमरीकी मिसाइलें, इस संतुलन को बिगाड़ने तथा सैनिक बढ़त हासिल करने के अलावा और कुछ नहीं है और इसे किसी भी हालत में मंजूर नहीं किया जा सकता है. और इसलिए सोवियत संघ ने मिसाइलों को घटाये जाने का भी प्रस्ताव दिया बशर्ते कि योरोप में नई मिसाइलें तैनात न की जाय. पर अमरीकी साम्राज्यवाद, सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों पर आक्रमण और युद्ध की वहशियाना मुहिम पर अड़े हुए हैं, और इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया है.

इस स्थिति में, सोवियत संघ के पास आज इनके सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया है कि वह अपनी, अपने सहयोगी देशों की तथा समाजवादी देशों की रक्षा की जिम्मेदारी पूरी करें, उसके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं रह गया कि नाभिकीय बढ़त तथा 'प्रथम प्रहार' की अपनी कोशिश में साम्राज्यवादियों ने जो खतरा पैदा कर दिया है उसका मुकाबला करने के लिए जबाबी कार्यवाई करें. और इस जिम्मेदारी को सोवियत संघ के नेतागण सही तरीके से निभा रहे हैं. यद्यपि, शांति के लिए, नाभिकीय अस्त्रों को परिसिमित करने के लिए इनके ओर से निरंतर तथा गम्भीर प्रयास जारी रहे साथ-साथ साम्राज्यवादियों के युद्ध साजिशों को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा की तैयारियों में भी बराबर सजग थी. समाजवादी राष्ट्रों की ये सजगता अमरीकी साम्राज्यवादियों की दुनिया पर हावी होने के इरादे पर पानी फेर रही हैं, दुनिया को साम्राज्यवादी साजिशों के गुलाम बनाने की इन युद्धोन्मादियों के योजनाओं को सफल होने में बाधा डाल रही है.

28 मई, 1983 को सोवियत सरकार ने यह घोषणा की कि अगर योरोप में अमरीकी मिसाइलें तैनात की गईं तो उसे भी मुकाबले के लिए जबाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, योरोप क्षेत्र में मध्यम-वर्गीय मिसाइलों पर एकतरफा रूप से लगाये गए प्रतिबंध को वापस लेना पड़ेगा, अमरीका तथा नाटो गठबन्धन द्वारा योरोप में नाभिकीय अस्त्रों की बढ़त के साथ संतुलन के लिए अमरीकी क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए नई योजनाएं बनाने में मजबूर हो जायेगी.

यह निहायत ही जरूरी और उचित कदम है. इन जंगखोरों को किसी भी हालत में सैनिक बढ़त हासिल करने नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका मतलब होगा समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ साम्राज्यवादियों को मदद करना. नाभिकीय बढ़त की अपनी कोशिश में साम्राज्यवादियों ने जो खतरा पैदा कर दिया है उसका मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ द्वारा जबाबी कार्रवाई किये जाने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं है.

मजदूर-वर्ग तथा दुनिया भर की जनता ने सोवियत संघ के इस रुख का स्वागत किया है क्योंकि यह दिखाता है कि साम्राज्यवादी ताकतें समाजवादी दुनिया को झुका नहीं सकती है. लेकिन, इसके साथ ही यह घटना स्थिति की गम्भीरता को रेखांकित करता है और बताता है कि आज भारत समेत दुनिया भर की जनता का तुरन्त हस्तक्षेप करना तथा उसका समय

रहते साम्राज्यवादी नाभिकीय दुस्साहसवादियों के नकेल डालना कितना जरूरी हो गया है.

भारत के मजदूर-वर्ग और ट्रेड यूनियन आन्दोलन को समझना चाहिए कि साम्राज्यवादी जिस युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं वह किन्हीं 'दो महाशक्तियों' का टकराव न होकर दो व्यवस्थाओं का टकराव होगा. साम्राज्यवादी शक्तियां, अब जापान की सहायता से, समाजवाद को—पिछले सौ सालों के संघर्ष में विश्व मजदूर-वर्ग की इस सबसे बड़ी कामयाबी को—मिटाने पर तुली हुई हैं. वे समाजवादी दुनिया को—विश्व के एक तिहाई हिस्से को—फिर से साम्राज्यवादी शोषण के लपेट में लाकर इन देशों के लोगों को गुलाम बनाना चाहती है. वे दुनिया को 1914 से पहले की स्थिति में देखना चाहते हैं, जिस समय समाजवादी शिविर का कोई अस्तित्व नहीं था और समूची दुनिया पर वे हावी थे वे फिरसे उन देशों की स्वतन्त्रता तथा आजादी को नष्ट करना चाहते हैं, जो समाजवादी शिविर के अस्तित्व में आने के बाद आजाद हुए थे, और फिर से पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं. और दुनिया पर हावी होने की साजिश में, यह समाजवादी शिविर सबसे बड़ा अवरोधक है.

इसलिए अगर युद्ध छिड़ता है तो यह समाजवाद को नष्ट करने और समूची दुनिया को गुलाम बनाने का युद्ध होगा, जिससे भारत भी बचा नहीं रह सकेगा. इसके लिए साम्राज्यवादी ताकतें हथियारों के इस्तेमाल का जुआ खेलने और करोड़ों की जानों की बली देने के लिए तैयार हैं. कुछ तो खुलेआम यह कह रहे हैं कि इस नाभिकीय युद्ध में दस करोड़ अमरीकी मारे जायेंगे फिरभी इस नाभिकीय युद्ध के फल खाने के लिए काफी अमरीकी बचे रहेंगे.

हमारे ट्रेड यूनियनों तथा मजदूर-वर्ग को युद्ध के इस खतरे को सबके सामने लाने में अपनी भूमिका अदा करनी होगी, और इस मामले में जनमत को गुमराह करने की जो सोची-समझी कोशिशें चल रही हैं उनके संदर्भ में सोवियत संघ के शांति प्रस्तावों को पूरा-पूरा समर्थन देना होगा. आप सभी जानते हैं कि कुत्सापूर्ण प्रचार के उद्देश्य से किस बेहया तरीकों से दक्षिण कोरियाई विमान दुर्घटना की योजना बनाई गई थी. उस उकसावेपूर्ण घटना की तुलना तो सिर्फ हिटलर की राइखस्टैग आगजनी की घटना से ही की जा सकती है समूची दुनिया ने छोटे से द्वीपिय देश ग्रेनाडा पर अमरीका का शर्मनाक हमला की भर्त्सना की है. और अब इस्राईली आग्रासियों के मदद में लेबनान में दखलअन्दाजी—इन सारी उकसावेपूर्ण युद्ध साजिशों को बेनकाब करना जरूरी हो गया है.

सत्ताधारी सरकार का रुख

देशभक्ति और जनतंत्र की दुहाई देने वाली ये सत्ताधारी सरकार—अमरीकी साम्राज्यवादियों की इस घृणित साजिशों की भर्त्सना करने से क्यों हिचकिचाति हैं ? बम्बई में हुई कांग्रेस अधिवेशन में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर पारित प्रस्ताव में अमरीकी साम्राज्यवादियों का जिक्र तक नहीं किया गया है. पर ये 'दो महाशक्तियों की बातें करती हैं. यह कहती है—

"शांति जैसे महान और जरूरी सवाल पर 'दो महाशक्तियों' के बीच वार्त्तालाप अब कारणों पर आधारित नहीं रह गई है. इन दोनों के बीच संघर्ष के कारण भी काफी है जिसे हल करना किसी भी विश्व संगठन के लिए शायद ही सम्भव हो. दुनिया के हर कोने में तनाव बढ़ रहे हैं और यह गहराता हुआ संकट मानव समाज को खतरे में डाल रहें है"

लोगों को यह समझाया जाता है कि इसके लिए दो महाशक्तियां जिम्मेदार है. शांति के पक्ष में बयान जरूर रखिए जैसे इंदिरा गांधी करती है' पर लोगों को युद्ध के खतरे के बारे में, इसके सही कारणों के बारे शिक्षित नहीं किजिए. सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के बयान से युद्ध को नहीं टाला जा सकता है शांति को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है. इसके लिए लोगों को लामबंद करना लाजिमी है जिसे कांग्रेस (आई) नहीं करती है—लोगों से इस खतरे के सही कारणों को छिपाती है.

बहरहाल, शांति के लिए एक औपचारिक समर्थन कम से कम युद्ध के लिए समर्थन या शांति के लिए कोई समर्थन नहीं से तो अच्छा है. सरकार के इस रुख के कारण भारतवर्ष में शांति के लिए संघर्ष आज कई गुना ज्यादा मुश्किल हो गया है.

चौतरफा संकट

भारत के सिलसिले में साम्राज्यवादियों की खास तौर पर यह रणनीति है कि उसे अपनी गुटनिरपेक्ष नीति तोड़ने तथा अपनी स्वाधीनता व संप्रभुता के मामले में समझौता करने के लिए मजबूर करने के लिए तथा सोवियत संघ से उनकी दोस्ती खत्म करने के लिए, उसके सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों की ओर से लगातार शत्रुता तथा युद्ध का खतरा खड़ा किया जाए. इसलिए पड़ोसी देशों में हो रहे जनवादी आंदोलनों को भारत विरोधी मोड़ दिया जा रहा है.

पाकिस्तान को एफ-16 तथा हारपुन मिशाइलों द्वारा सुसज्जित करना अमरीकी साम्राज्यवादी साजिशों का एक अंश है. दूसरी ओर बंगलादेश में तानाशाह एरशाद है जो गैर-कानूनी प्रवेश को रोकने के लिए भारत द्वारा लगाई जा रही घेरा के प्रश्न पर भारत विरोधी एक तनाव पूर्ण वातावरण पैदा करने की धमकी दे रहे हैं. और फिर नैपाल में एक हिन्दू

राजा है. जो दोनों देश के बीच एक दरार पैदा करने पर लगे हुए हैं. हालांकि नेपाल के कुछ यथार्थ शिकायतें हैं पर इसे साम्राज्यवादियों के उकसावे पर दोनों देशों के लोगों के बीच घृणा पैदा करने के काम में लगाए जा रहे हैं और फिर बौद्ध धर्मावलम्बी श्रीलंका है जिसके राष्ट्रपति ने पिछले जुलाई अगस्त में भारतीय मूल के तमिल अल्प संख्यकों के नरसंहार के दौरान खुले आम भारतवर्ष की भर्त्सना की और अमरीका ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादियों से सहायता की मांग की. भारत के तटवर्ती श्रीलंका वाली त्रिकोमाली अब अमरीकियों के कब्जे में है और इसे करीब करीब अमरीकी नौसेना अड्डा बना दिया गया है.

भारत के पड़ोसी देशों के एक तांत्रिक तथा फौजी शासन तंत्र के कारण हमारे देश की तथा उनके अपने देशों की भी आजादी खतरे में है. इस लिए पड़ोसी देशों में होने वाली जन-बाद की लड़ाई में हमारे देश के जनवादी आंदोलन तथा मजदूर वर्ग का गहरा हित है और इसलिए ये उसका समर्थन करते हैं जिससे जनतंत्र को कुचलने वाले अधिनायक वादी तथा साम्राज्यवादी शक्तियों को रोका जा सके.

पाकिस्तान के फौजी शासक के खिलाफ उस देश की जनता के बहादुराना संघर्ष एक खास अहमियत रखता है क्योंकि इस जनवादी आंदोलन की सफलता ही इस उपमहादेश में तमाम मुक्ति आंदोलनों के शक्तियों को मुक्त कर देगी और इस तरह तमाम अधिनायकवादी आधार टूटकर बिखर जायेंगे और इस देश की जनवादी शक्तियों को और शक्तिशाली बनायेंगे.

पर जिया अपने लोगों पर बर्बर दमन जारी रखा है. मर्द औरत, बच्चों सभी पर अत्याचार, समान रूप से जारी है. संघर्ष का केन्द्र बिन्दु सिंध में बहुत सारे लोग मारे गए. कुरान को मानने वाला एक इस्लामी राष्ट्र में आम लोगों (जिसमें सभी मुसलमान हैं) पर इसी तरह का वर्ताव किया जाता है. इस्लामी भाई चारा और इस्लामी राज्य का नारा लोगों को अलग रखने तथा उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने की शासक वर्ग की एक चाल है. उस समय की पूर्वी पाकिस्तान में बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं, बंगलादेश का बनना तथा पाकिस्तान के वर्त्तमान आंदोलन—सभी इस बात का सबूत है. धर्म के नाम पर लोगों के पास अपील, अपने शोषकों के खिलाफ तमाम मेहनतकशों की, पूंजीवादी शोषन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मजदूरवर्ग की एकता में फूट डालने के लिए की जानेवाली एक प्रतिक्रियाशील अपील मात्र ही है.

अगर पाकिस्तान में लोगों के रोष कुछ ठंडे हो रहे हैं तो अन्य पड़ोसी देशों के लोग चुप नहीं बैठे हैं. बंगलादेश में कई पार्टियों ने सैनिक शासन की समाप्ति, संसदीय प्रणाली की पुनर्बहाली तथा चुनाव की मांग करते हुए व्यापक आन्दोलन शुरू कर दिया है. नेपाल में पंचायती राज का चकमा देखने को मिला जिसके खिलाफ लोगों की आवाज बुलन्द हो रही है. मुस्लिम सैनिक शासक जिया और नेपाल के हिन्दू राजा, दोनों ही समान रूप से राजनीतिक पार्टियों का विरोध करते हैं, अर्थात् ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी संगठन जनता की मांगों को लेकर उन्हें लामबंद करें. वे यह चाहते हैं कि लोगों में अलगाव रहे ताकि बिना कोई रुकावट के वे अपना राज कायम रख सकें. मुट्ठीभर लोगों के हितों की रक्षा करने वाले, ये जनतन्त्र विरोधी शासक-वर्ग इसलिए आर्थिक सहायता आदि के लिए साम्राज्यवादियों की ओर झुकते हैं और उनके प्रभाव में आ जाते हैं.

श्री लंका के लोगों को एक दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ा. यहां की प्रतिक्रियावादी सरकार तमिल अल्पसंख्यकों के समस्याओं को, न्यायपूर्ण और समानता के आधार पर हल नहीं कर पाई और तमिलों को कत्लेआम, लूट, आगजनी का शिकार बनाया. इन सारी घटनाओं से घबराकर अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ने के लिये श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने साम्राज्यवादियों को अपनी सहायता के लिये बुलाया. और इसे जातियता का रंग देने के लिये भारत द्वारा आक्रमण किये जाने का प्रचार किया, जिससे यह प्रतीत हो कि श्रीलंका की आजादी खतरे में है और अपने बचाव के लिए ही अमरीकी मदद मांगी गई है.

पूंजीपति-भूस्वामी शासकवर्ग की असफलता

पाकिस्तान में बेचैनी, श्रीलंका की वारदातें आदि भारत की ही तरह इन देशों में भी जन-असंतोष का वही कारण है—जनवादी व्यवस्थाओं के आधार पर अपनी जनता की आर्थिक-सामाजिक समस्याएं हल करने में तीसरी दुनिया के पूंजीपति-भूस्वामी शासकवर्ग की असफलता, अपने देशों के अल्पसंख्यकों की समस्याओं को जनवादी तरीकों से हल करने में असफलता.

केन्द्र-राज्य सम्बंध

यही वजह है कि राज्यों के लिए समान दर्जे की मांग हमारे देश में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के पुनर्गठन की रचनात्मक मांग के रूप में उभरकर सामने आई है. पूंजीवादी व्यवस्था में राज्यों के अविलम्बिता से आर्थिक विकास सम्भव नहीं है. आसाम इसी पिछड़ेपन का शिकार है. इसके अलावा भारत के संविधान में राज्यों को बहुत कम अधिकार मिले हुए हैं. देश में कृषिक क्रांति और जनता के हाथों में अधिक अधिकार से ही राज्यों के द्रुत और समान आर्थिक विकास सम्भव है, इस बात की अगर समझदारी नहीं है तो विच्छिन्नतावादी और फूटपरस्त शक्तियां जनता को भ्रमित करने में सफल होती रहेंगी. और देश को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर साम्राज्यवादियों को हमें फिर से गुलाम बनाने की साजिशों में मददगार साबित होगी.

राज्यों द्वारा यह मांग की गयी है कि सभी राज्यों के साथ एक सा बर्ताव किया जाय तथा केन्द्र-राज्य सम्बन्ध समानता पर आधारित हों. एक आम मांग यह है कि आर्थिक तथा वित्तीय प्रशासन के मौजूदा अतिकेंद्रिकृत रूप को घटाना होगा, यद्यपि सुरक्षा तथा अन्य जरूरी जिम्मेदारियां केन्द्र की होंगी. इस हस्तांतरण से केन्द्र कमजोर नहीं होगा बल्कि उसका आधार मजबूत होगा. मजदूर वर्ग को इस मांग का समर्थन करना चाहिए.

अधिनायवाद के खिलाफ संघर्ष में तथा जनतंत्र की बहाली की लड़ाई में, सी पी आई(एम) की अगुवाई में वाम-शक्तियों के सामने कांग्रेस(आई) को पीछे हटना पड़ा. पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में तथा अगरतला म्यूनिसपल चुनावों के शानदार विजय ने देश की वाम शक्तियों को और भी शक्तिशाली बना दिया है.

बिगड़ती हुई कानून व व्यवस्था, भ्रष्टाचार

देश में जड़ जमाये बैठे चौतरफा संकट के साथ बिगड़ती हुई कानून तथा व्यवस्था की स्थिति—आम नागरिकों के जीवन के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है. डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अधिकारी चुप बैठे सब देख रहे हैं. इन समाजविरोधियों को खुली छूट मिल रही है, पर लोगों के, मजदूर-वर्ग के, जनवादी आन्दोलनों को कुचलने में यही अधिकारीगण कोई कसर नहीं छोड़ते. पिछले कई महिनों में सीटू के सदस्यों को जिस भयानक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा उसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं.

भ्रष्टाचार, शासक पार्टी के नेताओं का एक आवश्यक 'गुण' बन गया है—उन लोगों के लिए एक जीवन पद्धति बन गया है. बनस्पति में मिलावट (टैलो घोटाला) जिससे सम्बन्धित लोग कांग्रेस (आई) के कहे जाते हैं, व्याप्त भ्रष्टाचार का एक नमूना है. खाद्य वस्तुओं में मिलावट की छूट कांग्रेस(आई) शासन की रीति बन गई है. इसी तरह का एक और काला कारनामा है कर्नाटक की घटना जिसमें जनता पार्टी के समर्थक एक निर्दलीय सदस्य को पैसे से खरीदने की कोशिश की गई. भ्रष्टाचार तथा अन्तर्द्वन्दों से शासक पार्टी क्रमशः क्षीण होती जा रही है. विश्व इतिहास के इस नाजुक घड़ी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात आज यह है कि हमारे देश में आज ऐसी एक सरकार शासन की बागडोर सम्भाली हुई है जिनके भ्रष्ट और स्वार्थी नेताओं को अपने देश की जिम्मेदारियों के प्रति एक टुक भी ख्याल नहीं है.

इस स्वार्थपूर्ण वातावरण में पंजाब का मसला दिन-प्रति-दिन गम्भीर होता जा रहा है जिससे राष्ट्र-विरोधी ताकतों को लोगों को विघटित करने में मदद मिल रही है. और यही वजह है कि असम के सवाल पर भी स्थिति को सामान्य नहीं बनाया जा सका. और जबतक शासक पार्टी अपने शासनतंत्र पर निर्भर करती है तथा अलगाववादी व पृथकतावादी साजिशों को पूरी तरह बेनकाब कर लोगों को लामबंद नहीं करती है तबतक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकती.

श्रीलंकावासी तमिलों तथा भारतीय मूल के लोगों का नरसंहार ने पूरे देशवासियों को स्तम्भित कर दिया है. आम जनता के समस्याओं को हल करने में नाकाम श्रीलंका के पूंजीपति-भूस्वामी शासक सिंहली बहुसंख्यकों को तमिल अल्प-संख्यकों के खिलाफ खड़ा कर दिया, यद्यपि सवाल अल्पसंख्यकों के समस्याओं तथा श्रीलंका सरकार की थी. एक और भी साजिश रची गई थी—अमरीका, जो कार्यतः त्रिकोमाली में अपना अड्डा बनाये हुए है श्रीलंका में ग्रेनाडा जैसी नाटक करने के लिए तैयार बैठा था. भारत सरकार ने स्थिति को सही तरीके से समझकर, शांति की स्थापना की प्रचेष्टा की. अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अबतक जातियता की आवाज उठाकर अमरीका को मदद के लिए बुला लिया गया होता जिसका मतलब होता श्रीलंका के भारतीय मूल के लोगों के लिए गुलामी तथा खुद भारत की आजादी के लिए खतरा. हम श्रीलंका के कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य वाम पार्टियों का अभिनन्दन करते हैं जिन्होंने अल्पसंख्यकों पर चलाये गए अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करते हुए श्रीलंका की तथा मजदूर-वर्ग की एकता के साथ एकजुटता का इजहार किया. श्रीलंका की अखंडता को बनाये रखना दोनों ही समुदायों के हित में होगी साथ-साथ यह भी जरूरी है कि संविधान में तमिलभाषियों के लिए समान अधिकार का प्रावधान की भी गारण्टी हो. हम आशा करते हैं कि भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री पार्थसारथी के सहायता से इन समस्याओं का एक स्थायी समाधान निकाला जा सकेगा जिससे तमिल और सिंहलियों के बीच स्थायी दोस्ती कायम हो सके तथा दोनों समुदायों के लोग एक साथ मिलकर उन जिम्मेदारियों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित कर सके जो उनके सामने हैं—और वह है अमरीकी साम्राज्यवादी साजिशों के खिलाफ श्रीलंका की अखंडता और एकता को कायम रखने का कर्तव्य, आर्थिक तथा लोगों के जनवादी अधिकारों को और व्यापक बनाने की जिम्मेदारी. यह मानी हुई बात है कि इस अर्थ-व्यवस्था में या वर्तमान सरकार द्वारा इन समस्याओं का हल होना नामुमकिन है फिरभी जिस फैसले से लोगों के बीच विश्वास पैदा होता है तथा उसे एकजुट संघर्ष के लिये लामबंद होने में सहायता करती है वर्तमान के लिए उसे मान लेना लाजिमी है.

फूट परस्त ताकतें

पंजाब में हो रहे साम्प्रदायिक हत्याओं का हमें कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए एक सम्प्रदाय के उग्रपंथियों द्वारा अन्य

सम्प्रदाय के लोगों की हत्या किए जाने कि इस बहशियाना मुहिम से पंजाब में साम्प्रदायिक दंगों का बातावरण सा बना हुआ है जिसके पिछे दरअसल उन राष्ट्रविरोधी फुट परस्त तत्वों का हाथ हैं जिन्हें विदेशों से मदद मिल रही है. यह और बात है कि पंजाब के लोग इस कायरतापूर्ण साजिस को नाकामयाब किया. पर देश द्रोही शक्तियां इस सीमा वाले राज्य में असम जैसा स्थिति बनाए रखने की निरंतर कोशिश जारी रखा है. हम पहले ही बता चुके है कि किस तरह इंदिरा सरकार की स्वार्थी नीतियां इनके लिए मददगार साबित हो रही है.

पर इन हत्याओं से अकाली नेतृत्व की विवशता का पता चलता है. इन्होंने हरबार इन हत्याओं कि भर्त्सना की पर इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. तमाम सिखों के हिमायती करने वाले इन नेताओं को क्या इतना अधिकार नहीं कि इन हत्यारे को लोगों के दुश्मन कह सके तथा इन दुष्कृत्य कारियों को विलगित कर इन घटनाओं को खत्म कर सके? नेतृत्व को इन अनुभवों से सबक लेना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि मांगों के औचित्य जो भी हो अगर इसके समर्थन के लिए किसी खास सम्प्रदाय को ही आह्वान किया जाय और उनसे धर्म के नाम पर समर्थन लिया जाय तो सारी चीजें साम्प्रदायिक उग्रवादियों के हाथों में चला जाता है. अकाली नेतृत्व को इन सवालों पर गौर करते हुए पंजाब में साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने की प्रयास करना चाहिए.

पंजाब तथा असम, देश में फूटपरस्त ताकतों की गतिविधियों का द्योतक है. यह जानना होगा कि पिछले छः महिनों में इन एजेंसियों कि गतिविधियां बढ़ रही है जैसा कि जुलूसों में, धार्मिक स्थानों में हो रहे झड़प तथा द्वंदों से पता चलता है. ऐसा लगता है कि कुछ ऐजेंसिया साम्प्रदायिक दंगों का मौका खोज रही है इस वातावरण में पैसों से, विभिन्न उपायों से, विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के बीच धार्मिक कट्टर पंथी भावों को उकसावा देने की प्रयास जारी है. हिन्दू एकात्मता तथा कई अन्य आह्वान किसी प्राचीन परम्परा के लिए अचानक चिंता या दिल चस्पी के कारण नहीं किया जा रहा है — यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने की साजिश से किया जा रहा है.

साथियों, शाषक वर्ग और सरकार इन आक्रमणों को रोकने में असमर्थ है. सरकार अपनी जिम्मेदारियां छोड़ सकती पर हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है — हम सिर्फ सरकार को दोषी ठहराकर खुश नहीं रह सकते. हमारे मजदूर वर्ग को इन शक्तियों के खिलाफ लड़ना होगा.

महंगाई

सामानों कि किमतों में तथा मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण हमारे लोगों को तथा मजदूरवर्ग को पिछले छः महीनों में और परेशानियां सहनी पड़ी. 1981-82 में मूल्य सूचकांक में (1960-100) में 13.4 फिसदी की वृद्धि हुई. इसी अवधि में चावल का थोक मूल्य में 22% की वृद्धि हुई, गेहूं का 9.8% दाल का 4.4% फल व सब्जियों का 11.2%, दुध तथा दूध से बनी चीजें 3.4% अन्य खाद्य बस्तुएं 47.2%, चाय की 58.2% खाद्य तेल 10.2%, दिसम्बर 1982 से जून 1983, इस समय के दौरान कीमतों में वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए रिजर्व बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया. "इस अवधि में चावल, दाल, तेल की कीमतों में वृद्धि का मूल्य सूचकांक पर बहुत दिनों तक प्रभाव रहेगा. मूल्यों का निर्धारण के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है" अर्थात् आने वाले दिनों में लगातार वृद्धि के लिए तैयार रहे. इससे खुदरा दरों का तथा इससे आम लोगों की हालत का अन्दाजा लगा सकते हैं. अब हम दो अंक वाले महंगाई का सामना कर रहे हैं और इस मुद्रा स्फीती के कारण अगस्त में रूपए का खरीद शक्ति सिर्फ 14.4 पैसे रहा. मूल्य सूचकांक में लगातार वृद्धि का प्रभाव लोग बहुत बूरी तरह महसूस कर रहे हैं.

पर सत्ताधारी कांग्रेस (आई) पार्टी इसकी जिम्मेदारी जनता सरकार पर थोप रही है और लोगों को यह बता रही है कि दरअसल कांग्रेस (आई) ने ही लोगों को बर्बादी से बचाया. देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर संतोष प्रकट करते हुए ए आई सी सी अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को जरा सुनिये, "जनता शासन काल में देश की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति में स्थिरतापूर्वक सुधार आने की ए आइ सी सी (आई) संतोष से नोट करती हैं. जनता शासन काल जिसमें राष्ट्रीय आय 5% घट गई थी, जब सामानों की कीमतों में 21.4% की वृद्धि हुई थी. इसके बिपरीत पिछले तीन सालों में हर तबके के लोगों के समर्थन प्राप्त कांग्रेस सरकार की कार्यकारी नीतियों के कारण राष्ट्रीय आय में औसत 5% के दर से बृद्धि हुई है, महंगाई पर रोक लगाई जा सकी है तथा अर्थनीति को स्वस्थ्य बनाया गया है"

दिल्ली दरबार के भांड द्वारा ही एसा मजाक करना सम्भव है दो करोड़ से भी अधिक बेकारों की फौज, महंगाई के बढ़ते आंकड़े, राष्ट्रीय उत्पादकता की हार में 1982-83 में सिर्फ 1 से 2% की वृद्धि जो पिछले दो सालों की वृद्धि के हार से कम है—इस पृष्ठ भूमि में अर्थनीति में सुधार आने की बात आम जनता के मुसिबतों के प्रति शासक पार्टी की क्रूरता की और उसकी असमर्थताओं को बेनकाब करती है. बढ़ती कीमतें तथा जनता की घटती क्रय शक्ति सरकार की हीन वित्त प्रबंधन के लिए अपनाई जा रही आर्थिक नीतिओं से जुड़ी हुई है. और यह इस लिए किया जाता है ताकि पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट के बोझ को मजदूरों तथा जनता के कंधे पर थोपा जा सके. इंदिरा कांग्रेसी सरकार दावा करती

है कि उसने लाखों लोगों को गरीबी की रेखा से उपर पहुंचा दिया है जबकि खाने-पीने की चीजों की तथा कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट आ रही है. कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत 1965 के 16.44 मीटर से घटकर 1981 में 14.76 तथा 1982 में 13.50 मीटर हुई है. (इसी 1981-82 वर्ष में अर्थ व्यवस्था में कांग्रेस सरकार द्वारा सुधार लाए जाने पर ए आई सी सी प्रस्ताव में संतोष प्रकट किया गया है). बढ़ती महंगाई के कारण जनता की क्रय शक्ति घट रही है. दूसरी ओर पूंजीपतियों के मुनाफे लगातार बढ़ रहे हैं और जब तक मजदूर वर्ग सरकार की जन विरोधी नीतियों का, उसकी बजट नीतियों का मुकाबला करने तथा उन्हें शिकस्त देने के लिए तैयार नहीं होगा वह अपने जीवन स्तर की रक्षा नहीं कर पाएगा.

लूट का बोलबाला

सरकार की आर्थिक नीतियां, बम्बई के कपड़ा मिल मालिकान को नाजायज तरीकों से मुनाफा कमाने की हिम्मत दिलाई. अपने बेतहाशा मुनाफे के लिए इन मिल मालिकान ने हड़ताल को लम्बा खींचकर दो लाख मजदूरों को भूखे मारकर झुकाने की कोशिश की थी और इसके चलते देश को करोड़ रू के उत्पादन से हाथ धोना पड़ा. जब कई लाख रू की बैंक डकैती होती है तो सनसनी फैल जाती है पर जब ये पैसे वाले मालिकान देश को 1200 करोड़ रू का नुकसान पहुंचाया तो उसे नजर अंदाज करते हुए मजदूरों को ही जिम्मेदार ठहराया गया. बम्बई कपड़ा मिल मालिकान के इस समाज विरोधी दृष्टिकोण तथा रूख की भर्त्सना की जानी चाहिए. जनता की महत्वपूर्ण आवश्यकता से सम्बन्धित इस उद्योग का प्रबंध ऐसे लोगों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है.

कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीय करण करो

तमाम ट्रेड यूनियनों को मिलकर कपड़ा उद्योग के तत्काल राष्ट्रीयकरण की मांग उठानी चाहिए क्योंकि यह मांग अब मजदूरों के नौकरी की सुरक्षा तथा आम जनता के हित से सम्बन्धित है. बम्बई मिलों में तीसरी पाली के काम बंद कर दिए गए हैं तथा अहमदाबाद में 15 प्रतिशत करघा को बंद कर दिया गया इन आक्रमणों का खात्मा तभी हो सकता है जब इस उद्योग से नीजी मिलकियत खत्म किया जाय. सीटू सरकार द्वारा 13 मिलों को अधिग्रहण किए जाने का समर्थन करता है 13 मिलों के अधिग्रहण का सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है उसीमें यह स्वीकार किया गया है कि जनवरी 1982 में हड़ताल शुरू होने से पहले ही इन मिलों की आर्थिक स्थिति बहुत ही असंतोषजनक थी. अचरज नहीं कि जिन 13 मिलों का अधिग्रहण किया गया है उनके मालिकान पर 270 करोड़ रू बकाया निकलता है — जिसमें 130 करोड़ रू बैंकों का ही है— जबकि मिलों में उनकी कुल पुंजी 12 करोड़ रू बैठती है. इन मिलों में 35 हजार मजदूर काम पर लगे हुए थे जिन्हें मालिकान ने पिछले 20 महीनों से बेरोजगार बना रखा था. यह कुप्रबंध तथा लूट की खुली मिसाल है जिससे निजी क्षेत्र के काम करने के तरीके तथा उसकी नैतिकता का अंदाज लगाया जा सकता है.

कपड़ा सेठों तथा फिक्की ने इस सवाल पर काफी शोर उठाया. इन लोगों ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एन टी सी) द्वारा पहले ही अधिग्रहित 103 मिलों का जिक्र करते हुए बताया कि जुलाई 1983 तक इसमें कुल नुकसान 432 करोड़ रू से भी ज्यादा है फिर भी सरकार इन 13 मिलों को अधिग्रहण कर रही है.

समानता के आधार पर मजदूरों की शिरकत

सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है जिसे हल करने की कोई लगन नहीं दिखाई गई. सवाल सिर्फ राष्ट्रीय करण किए जाने का नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा 103 मिलें या अब अधिगृहीत यह मिलें उस समय तक दक्षतापूर्वक नहीं चलाई जा सकती जब तक कि उनके मैनेजमेंट में समानता के आधार पर मजदूरों की शिरकत नहीं होती. सीटू की यह बराबर की मांग रही है पर सरकार तथा नीजि क्षेत्र दोनों के लिए ही यह कतई मंजूर नहीं.

सरकार एवं निजी क्षेत्र के मालिकानों के सुविधा के लिए हम रिजर्व बैंक के गवर्नर डा. मनमोहन सिंह की बात को दोहराना चाहेंगे. उन्होंने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के भाषण में सभी उद्योगों को चलाने के मामले में मजदूरों की शिरकत की इस सच्चाई को स्वीकार किया. उन्होंने यह भी बताया कि औद्योगिक सम्बन्धों के प्रश्न पर हमारे उद्यमकर्त्ता या व्यवस्थापकों को एक कारगर तथा स्थायी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी हो गया है. यह दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए—जो मजदूरों को समानता के आधार पर शिरकत करने की या भागेदारी के लिए मददगार साबित हो, जिसमें ट्रेड यूनियनों को जनवादी नीति की महान और जरूरी ढांचा समझा जाय तथा जिससे मुट्ठीभर मालिकान के प्रभाव से मनमाने ढंग से जन-हितकारी नीतियों को बदला न जा सके. (आर बी आई बुलेटिन मार्च 1983).

जूट उद्योग

मगर पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग की हालत तो बम्बई के कपड़ा मिलों से भी ज्यादा खराब है. जूट उद्योग के मामले में भयंकर हेराफेरी और उद्योग द्वारा हजारों मजदूरों को

बेरोजगार बनाये जाने के चलते राष्ट्रीयकरण तत्काल आवश्यक हो गया है. इंटक समेत राज्य में सक्रिय तमाम ट्रेड यूनियनों ने इस मांग को स्वीकार किया है यही नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी— मतभेदों के बावजूद राज्य विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव के जरिये यह मांग की है और विधानसभा के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमन्त्री को यह ज्ञापन दिया है. फिर भी, केन्द्र सरकार इस पर कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है और उद्योग के निजी मालिकान पर अपना बरदहस्त बनाये हुए हैं.

दूसरी ओर जूट सेठ तालाबंदियों का इस्तेमाल करते रहे हैं. 1982 में 115 तालाबंदियां की गई थीं और 1981 में 117. इसके विपरीत इसीदौर में हड़ताल के आंकड़े 43 फीसद से गिरकर 29 फीसद रह गये थे. इस समय 19 जूट मिलों में तालाबंदी या मिलबंदी के कारण 63,400 मजदूर प्रभावित हैं.

इसलिए, आश्चर्य की बात नहीं है कि मालिकान लगातार 1979 के त्रिपक्षीय सम्मेलन के फैसलों को लागू करने से इंकार करते रहे हैं. ये मालिकान ग्रेडों तथा वेतनमानों और काम के सिलसिले में श्रममंत्री की सिफारिशों को लागू करने से इन्कार करते रहे हैं. ये मालिकान मजदूरी में बढ़ोतरी करने या ट्रेड यूनियनों की दूसरी किसी मांग को पूरा करने से भी इन्कार करते रहे हैं. मालिकान के इस अड़ियल रवैये के कारण ही ट्रेड यूनियनों को संयुक्तरूप से जनवरी 1984 से अनिश्चित-कालीन हड़ताल का फैसला करना पड़ा है.

हमारे तमाम यूनियनों को सिर्फ जूट उद्योग के मजदूरों की मांग का समर्थन ही नहीं बल्कि उन्हें इस प्रश्न पर मजदूरों के बीच सक्रियता से प्रचार करना है. हमें चारों ओर से केन्द्र सरकार पर इतना दबाव डालना होगा कि वह इन मांगों को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाय.

साथियो, हमारी सरकार की नीति ही कुछ अलग सी है. सरकार जिस तरह पहले से अधिगृहित कारखानों के प्रबन्ध को उनके पुराने मालिकान को लौटाने (डिनोटिफिकेशन) की नीति पर चल रही है उसे देखते हुए राष्ट्रीयकरण की मांग और भी जरूरी हो जाती है.

तालाबंदी—मालिकान का नया हथियार

साथियो, कानपुर में सम्पन्न हमारे पांचवें सम्मेलन में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया था कि मजदूरों के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए और उन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर करने के लिए मालिकान लगातार बढ़ती हुई तादाद में तालाबंदियों का सहारा ले रहे हैं. इन तालाबंदियों के समाज-विरोधी चरित्र पर खास तौर पर गौर किया जाना चाहिए कि इस तरह मजदूरों को झुकाने के लिए, भूखों मारने का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है. इस तरह उनके जनवादी अधिकारों तथा अपने श्रम के जरिए रोजी कमाने के बुनियादी अधिकार को मजाक बनाकर रख दिया गया है. और यह सब हो रहा है मुट्ठीभर सेठों की मुनाफे की भूख को संतुष्ट करने के लिए. यह अत्याचार अभी भी जारी है.

अखबारों में छपे इन आंकड़ों से ये जाहिर है कि कुल नष्ट हुए श्रम दिनों में तालाबन्दियों का हिस्सा हड़तालों से ज्यादा है :

नष्ट हुए श्रम-दिवस (लाखों में)

वर्ष	हड़तालें	तालाबंदियों	कुल
1980	120(55%)	99(45%)	219
1981	212(58%)	153(42%)	366
1982	156(47%)	177(53%)	334
1983 (जनवरी से मई)	49(48%)	53(52%)	101

(बम्बई कपड़ा उद्योग में हड़ताल इसमें शामिल नहीं है)

1982 में तथा 1983 के पहले पांच महीनों में 50 फीसद से भी ज्यादा श्रम दिवस तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए. बम्बई कपड़ा उद्योग में दरअसल मालिकान ने ही हड़ताल को लम्बा खींचा जो कि तालाबन्दी ही समझी जा सकती है. श्रम सम्मेलन में पेश की गई सरकारी आंकड़ों में भी यह तथ्य स्वीकार किया गया है.

पर यह दिखाने की एक निरन्तर कोशिश रही है कि तालाबन्दियों से हड़तालों के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवस ज्यादा है. आंकड़ों की यह विचित्र कतर-ब्योंत भी सरकारी ज्ञापन के साथ पेश किया गया था :

उत्पादन में हुई हानि (करोड़ों में)

वर्ष	हड़तालों से	तालाबंदियों से	कुल
1980	172.51	124.53	297.54
1981	465.11	163.66	628.76
1982	123.69	51.01	174.69
1983(मई तक)	26.11	20.37	46.49

1981 में नष्ट हुए श्रम दिनों में 42 फीसद तालाबन्दियों में नष्ट हुए थे लेकिन उत्पादन में हुई हानि सिर्फ 25 फीसद दिखाई गई थी. इसी तरह 1982 में 53 फीसद श्रम-दिन तालाबन्दियों में नष्ट हुए थे लेकिन इसके कारण उत्पादन में हानि सिर्फ 43 फीसद दिखाई गई थी. क्या तालाबन्दियों और हड़तालों का ऐसा कोई क्षेत्र विभाजन हो गया है कि ताला-

बन्दियां सिर्फ कम मूल्यवाले मालों तक ही सीमित रहेंगी जबकि हड़तालें ज्यादा कीमत वाले मालों के कारखानों में होंगी.

बीमार उद्योग

बीमार उद्योगों की तेजी से बढ़ती संख्या से ऐसा लगता है कि औद्योगिक बीमारी—मंदी तथा कुप्रबन्ध का सभ्य सरकारी नाम है.

भारतीय रिजर्व बैंक के 1982-83 के आंकड़ों से पता चला है कि एक करोड़ रु. तक वित्तीय सहायताप्राप्त बीमार इकाईयों की जून 1982 के अंत तक संख्या थी 439 जिन्हें कुल 1728.40 करोड़ रु. की सहायता दी गयी है. 1981 जून के अन्त तक ऐसी इकाईयों की संख्या 422 थी जिनके पास बैंकों का कुल कर्ज 1429.29 करोड़ रु. निकलता है. बैंकों द्वारा शिनाख्त की गई बीमार 439 बड़ी इकाईयों में 374 में जांच पड़ताल के बाद यह बताया गया है कि इनमें से 320 को चलाई जा सकती है जिसका मतलब है कि अन्य 50 इकाईयां स्थाई रूप से बन्द कर दी जायेंगी. जून 1982 के अन्त तक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों में शिनाख्त की गई 26,973 बीमार इकाईयों को दिये गए कर्ज का परिणाम 393.67 करोड़ रु. था जबकि 1981 के इसी अवधि में 22,360 इकाईयों को 321.93 करोड़ रु. दिए गए थे. इसमें 14,576 इकाईयों को चलाये जाने के अयोग्य बताया गया जिसका अर्थ है इन्हें बन्द कर देना चाहिए. रिजर्व बैंक के ये आंकड़े मंदी, कुप्रबंध और दिवालियापन की तस्वीर पेश करती है. छोटी इकाईयों के मामले में औद्योगिक बीमारी महामारी की तरह फैल रही है और पिछले एक साल में ही ऐसे बीमार छोटे उद्योगों की संख्या 20 फीसद बढ़ी है. इनमें से ज्यादातर इकाईयां बन्द होने जा रही हैं. इस बीमारी को तभी रोका जा सकता है जब मजदूरों को विश्वास में लिया जाय और प्रबन्ध की जिम्मेदारियों में शरीक किया जाय; बड़ी बीमार इकाईयों का राष्ट्रीयकरण किया जाय तथा साथ ही उनके प्रबन्ध में मजदूरों को हिस्सेदार बनाया जाय जबकि छोटी इकाइयों को समय रहते मदद की जाय. इन कदमों तथा मजदूरों के शिरकत के जरिये ही बीमार इकाईयों को फिर से खड़ा किया जा सकता है.

मजदूर प्रतिनिधी कौन ?

हाल में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन से यह जाहिर होता है कि इंदिरा कांग्रेसी शासक, मजदूरों को अपने प्रतिनिधी अपने आप चुनने का अधिकार नहीं देना चाहते, इसके बजाय वे उन पर अपनी मर्जी का संगठन थोपना चाहते हैं जो उनके दबाव के आगे झुक सके जैसा बम्बई कपड़ा मजदूर हड़ताल के दौरान देखने में आया. अक्सर यह संगठन इंटक ही होता है. सीटू हमेशा से इसके लिए गुप्त मतदान के पक्ष में रही है ताकि जब कोई समझौता हो, मजदूरों के बहुमत की राय उसके साथ हो. केन्द्र सरकार न तो खुद इस सिद्धान्त को स्वीकार करती है और न राज्य सरकारों को ही इसे स्वीकार करने की इजाजत दे रही है. पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री के इस सुझाव को भी ठुकरा दिया है कि दस साल से चले आ रहे अपूर्ण विचार विमर्श के इंतजार में बैठे रहने के बजाय राज्यों को इस मामले में अपनी व्यवस्थाएं खुद तय कर लेने का अधिकार दे दिया जाय. इसी दृटिकोण से पं बंगाल विधान सभा द्वारा पारित ट्रेड यूनियन संशोधन बिल 1983 के लिए हम पं बंगाल श्रम मंत्री तथा वाम मोर्चे वाली सरकार का अभिनन्दन करते हैं. पर क्या इसे सरकार मान लेगी ? इन सारे सवालों के लिए ही केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के पुनर्गठन की रचनात्मक मांग और भी जरूरी हो गया है.

ट्रेड यूनियन एकता का निर्माण

इन परिस्थितियों में ट्रेड यूनियन एकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है. आज जब मजदूर वर्ग पर तालाबंदी मिलबंदी, छंटनी, आदि के रूप में हमले बढ़ रहे हैं, एकता के आह्वान को अनदेखी कोई नहीं कर सकता है. यही वजह है कि एकता तथा संयुक्त कार्रवाई की अपील का असर मजदूरों के लगातार बढ़ते तबकों तथा अधिकाधिक संगठनों पर हो रहा है और इसके लिए ज्यादा समर्थन मिल रहा है.

खास तौर पर पं. बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में एवं किसी हद तक दूसरे सभी राज्यों में भी संयुक्त कार्रवाईयों के इस ढांचे को आगे बढ़ाने में बार बार सफलताएं मिली है. केन्द्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठण के सवाल पर पं बंगाल का सितम्बर का जबरदस्त बंद, जूट मजदूरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का संयुक्त आह्वान, केरल में करूनाकरण सरकार तथा मालिकान के प्रतिक्रियाशील नीतियों के खिलाफ बार-बार हुई संयुक्त कार्रवाइयां जिनमें कई बार इंटक की यूनियनें भी शामिल हुई थी, एम जी आर सरकार के विधेयक के खिलाफ एटक तथा डी एम के के साथ संयुक्त कार्रवाइयों, इसी की मिशालें हैं.

इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं. इस्पात तथा कोयला उद्योगों में सीटू से सम्बद्ध मजदूर फेडरेशनें अधिकारियों को ऐसे नए समझौतों के लिए बाध्य करने में कामयाब हुई है जिनमें मजदूरों की अनेक फौरी मांग स्वीकार की गई है तथा इन उद्योगों में बुनियादी न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ी है.

इस संकटपूर्ण आर्थिक परिस्थिति में कोयला, इस्पात तथा

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में हुए वेतन समझौते मजदूर वर्ग की एकता और एकबद्धता के शक्ति का द्योतक है.

लेकिन, इसके साथ साथ हमें यह भी जानना होगा कि सीटू तथा अन्य संगठनों के पीठ के पिछे किए गए समझौते (बंगलौर के समझौते जैसा) भी हैं जो एकता की भावना के साथ विश्वास घात करके किए गए हैं. इनमें से हर समझौता मजदूरों के हितों के खिलाफ गया है और मजदूरों ने इन पर, अपने गुस्से का इजहार भी किया है. इस तरह के समझौते में ऐसा होना ही स्वाभाविक है क्योंकि ये समझौते प्रबंधकों के साथ मिलीभगत का फल है.

केन्द्र सरकार द्वारा अपने सारे कर्मचारियों के लिए बोनस की मांग स्वीकार किए जाना, केन्द्र सरकार कर्मचारियों के आंदोलन की एक महत्वपूर्ण प्रगति है. यह सफलता कर्मचारियों के सभी तबकों को एकजुट करने के अथक प्रयासों तथा अन्य फेडरेशनों द्वारा दिए गए समर्थन से ही संभव हुई है. इस एकता की रक्षा करनी होगी और उसे मजबूत बनाना होगा.

केन्द्र सरकार कर्मचारियों के आंदोलन की अति विभाजन तथा विभागी करण की बात हमें पसंद नहीं. यह भविष्य में खतरे का कारण बन सकती है. अगर कर्मचारी अपने विभागों, अपनी विशेष मांगों पर ही ध्यान देते रहेंगे तो अधिकारियों को उन्हें विभाजित करने का मौका मिल जाएगा. सरकार ने एक हाथ से जो दिया है उसे आने वाले महीनों में दूसरे हाथ से छीनने की कोशिश करेगी, इस लिए हम आशा करते हैं इन कमजोरियों से उपर उठकर अपनी एकता को ये और व्यापक और मजबूत करेंगे. केन्द्र सरकार कर्मचारियों के काम का बोझ बढ़ाने, स्टाफ कम करने आदि की सरकार की कोशिशों के बारे में हमें आशा है कि ये सतर्क रहेंगे.

राष्ट्रीय अभियान समिति

साथियों, महासचिव की रिपोर्ट में राष्ट्रीय अभियान समिति के बारे में बताया गया है. हमारे सम्मानित नेता का. पी. राममूर्ति ने भी सीटू मजदूर में एक लेख में राष्ट्रीय अभियान समिति के दूसरे सम्मेलन के महत्व तथा हमारे जिम्मेदारियों पर समुचित प्रकाश डाला है. इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि सम्मेलन से ट्रेड यूनियन एकता के संघर्ष में हुई प्रगति को सुदृढ़ करने में मदद मिली है. कामगार महिलाओं का कन्वेन्शन, तालाबंदी विरोधी कन्वेन्शन आदि बुलाने के सम्मेलन के फैसले का हम स्वागत करते हैं.

हमारा अनुभव से यह साफ हो रहा है कि एकता तथा संयुक्त कार्रवाई की अपील का असर मजदूरों के व्यापक हिस्से तथा अधिकाधिक संगठनों पर हो रहा है. इसलिए आम समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए, एकता को बढ़ाने के लिए तथा मौजूदा बदहाली के हालत से लोगों को कुछ राहत दिलाने के उद्देश्य से समाज की अर्थ व्यवस्था का रूप रेखा तैयार करने के लिए—सभी ट्रेड यूनियनों का एक कन्फेडरेशन की गठन की मांग को हम पुनः दोहराते हैं. खेत मजदूरों तथा किसानों की बढ़ते बदहालि की स्थिति से मुक्त करने के लिए भी हमें सब कुछ करना होगा.

वर्तमान संकट पूर्ण स्थिति के बावजूद जनता के हितों की रक्षा के लिए जो कुछ भी किया गया है उसके लिए हम प. बंगाल तथा त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकारों की सराहना करते हैं. हम उनका अभिनंदन करते हैं क्योंकि उन्होंने इंदिरा कांग्रेस के सारे उकसावों के बावजूद जनता के जनवादी अधिकारों की रक्षा तथा विस्तार करने का शानदार रिकार्ड कायम किया है. हम उन्हें जनवाद की अग्रिम चौकियां समझते हैं जिन्हें हमारे सभी यूनियन, हमारा सीटू तथा तमाम ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा सुरक्षित रखना पड़ेगा.

मार्क्स की शिक्षा

साथियों, मार्क्स की मृत्यु शताब्दी के इस बर्ष में ट्रेड यूनियनों के काम के बारे में मार्क्स की शिक्षा को याद रखें "ट्रेड यूनियनों का काम है मजदूर वर्ग में अपने महान् ऐतिहासिक मिशन की चेतना पैदा करना, उनमें मजदूरी की गुलामी की व्यवस्था मात्र के खिलाफ कार्रवाई की अपनी शक्ति का पूरा पूरा अहसास पैदा करना और उन्हें सच्चे सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलनों में उतारना".

"उन्हें अब मजदूर वर्ग की पूर्ण मुक्ति के व्यापक हित में उसके संगठन केन्द्र के रूप में समझे-बूझे ढंग से काम करना सिखना होगा. उन्हें इस दिशा में जाने वाले हर सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन की मदद करनी होगी. खुद को समूचे मजदूर वर्ग का अगुआ तथा प्रतिनिधि मानते हुए और उसी के रूप में काम करते हुए—उन्हें खेतमजदूरों जैसे सबसे कम मजदूरी वाले व्यवसायों के हितों को अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए जिन्हें विशेष परिस्थितियों ने शक्ति हीन बना दिया है. उन्हें सारी दुनियां को विश्वास दिलाना होगा कि उनके प्रयास संकीर्ण तथा आत्मकेन्द्रित नहीं बल्कि लाखों पद दलितों की मुक्ति उनका लक्ष्य है".

संपादक मंडल

पी. राममूर्ति (चेयरमेन)

मनोरंजन राय, नीरेन घोष, सुधीन कुमार,
एम. एम. बारेंस, पी. के. गंगुली

एम. के. पंधे (सम्पादक)

सीटू कार्यकारिणी बैठक का आह्वान

✻ शांति संघर्षों को तीव्र करो !

✻ तालाबन्दी, क्लोजर व मंहगाई के खिलाफ संघर्ष करो !

जमशेदपुर में 30 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. कानपुर में सम्पन्न सीटू के पांचवें सम्मेलन के बाद की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचारात्मक विश्लेषण तथा इन परिस्थितियों के मुकाबले के लिए संघर्षों एवं सांगठनिक काम-काज पर विचार-विमर्श किया गया.

बैठक में 72 सदस्यों ने शिरकत की. इसके अलावा सुजीत दास, नारायन साहा (अ. भा. पथ परिवहन कर्मचारी फेडरेशन) तथा एस. पुन्यवती (अ. भा. कामगार महिला समन्वय समिति) ने आमंत्रित के रूप में उपस्थित रहे.

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने बैठक के पहले लाल झंडा फहराया और शहीद स्तम्भ पर फूल चढ़ाकर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजली अर्पित की. लाल कमीज पहने हुए सौ से भी अधिक वालंटियरों ने लाल झंडा का अभिवादन किया.

सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए बिहार राज्य सीटू के अध्यक्ष योगेश्वर गोप ने अपना स्वागत भाषण पढ़ा.

दिवंगत का. एम. आर. वेंकटरमण, का. हृषि बनर्जी, का. निरोद चक्रबर्ती अन्य शहीदों पर का. पी. राममूर्ती द्वारा शोक प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद का. बी. टी. आर ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया.

प्रस्ताव उपसमिति : निम्नलिखितों को लेकर प्रस्ताव उपसमिति का गठन किया गया :

पी.के. गांगुली(संयोजक), शिवाजी पट्टनायक, के. रमाणी, के. एन. रवीन्द्रनाथ, सुनील बसुराय तथा बीरेन राय.

क्रिडेसियल उपसमिति : इस उपसमिति में पी. सत्यनारायण (संयोजक), एन. पद्मलोचन तथा रघुनाथ कुशारी थे.

महासचिव की रिपोर्ट

का. समर मुखर्जी ने, उसके बाद, महासचिव की रिपोर्ट पेश की. अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्थिति तथा सीटू एवं मजदूर-वर्ग द्वारा चलाये जा रहे संघर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने खास तौर से युद्ध के बढ़ते खतरे की ओर ध्यान आकर्षण कराया और कहा इंग्लेंड तथा प. जर्मनी में नयी मिसाइलें तैनात करने की रीगन प्रशासन का फैसला जेनेवा वार्ताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से ही किया गया है. इस संदर्भ में उन्होंने विभिन्न ट्रेड यूनियनों के सहयोग से शांति आन्दोलनों को लगातार चलाये जाने की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने, मजदूर-वर्ग के हित में तथा समाजवाद की रक्षा के लिए, सीटू यूनियनों को एक सबसे शक्तिशाली युद्ध-विरोधी शक्ति के रूप में उभरने के लिए आह्वान किया. बढ़ती हुई महंगाई तथा तालाबंदी, क्लोजर एवं छंटनी के रूप में मालिकान तथा सरकार के बढ़ते हमले की ओर इशारा करते हुए बताया कि मजदूर-वर्ग के ऊपर अपने गहराते संकट के बोझ को लादने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जा रहा है. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से शर्मनाक शर्तों पर लिए गए कर्ज से संकट और भी गम्भीर हो गया है. उन्होंने संघर्ष के नये तरीके अपनाते हुए तथा संगठन को और भी शक्तिशाली बनाकर इन नये हमले का मुकाबला करने को आह्वान किया.

सीटू के सचिव का. नृसिंह चक्रबर्ती ने तालाबंदियों, क्लोजर औद्योगिक रूग्णता तथा छंटनी के बारे में विस्तार से व्याख्या करते हुए बताया कि इसके कारण बेरोजगारों की कतार और लम्बी होती जा रही है. उन्होंने भी आन्दोलन के नये रूप अपनाने की बात बताई तथा यूनियनों से तालाबंदियों व क्लोजर सम्बन्धी तथ्य भेजने के लिए आग्रह किया.

महासचिव की रिपोर्ट पर बहस

महासचिव की रिपोर्ट पर बहस में भाग लेते हुए मोहम्मद अमीन (प. बंगाल) ने जूट उद्योग की स्थिति के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि जूट उद्योग में दरअसल कोई संकट नहीं है. जूट सेठों द्वारा बेतहाशा मुनाफा कमाया जा रहा है फिरभी और मुनाफा लूटने के इरादे से ये लाखों मजदूरों तथा जूट उत्पादकों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा कर दिया. जूट की खपत पिछले दसक के दौरान 3.5 लाख से बढ़कर 10 लाख टन हो गई है; निर्यात के मामले में ये विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं जिसके कारण निर्यात की गति भी धीमी हो गइ है; भारत सरकार सोवियत संघ को भी जूट भेजने से इंकार कर दिया है. इस साल भी अच्छे उत्पादन की उम्मीद है पर भारत सरकार के संरक्षणप्राप्त ये मालिकान घोर मजदूर-विरोधी रुख जारी रखते हुए समझौते को तथा प. बंगाल श्रममन्त्री के सिफारिशों को लागू करने से इंकार कर रही है. वर्षों के संघर्ष

ने आज प. बंगाल में एक बेमिशाल स्थिति पैदा कर दी है जिसके कारण इंटक सहित तमाम ट्रेड यूनियनों तथा कांग्रेस(आई) सहित सभी राजनीतिक पार्टियों ने संयुक्तरूप से समूचे जूट उद्योगों का राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे हैं तथा इस मांग की पूर्ती के लिए संयुक्तरूप से 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है.

स्टील वर्कर्स फेडरेशन के जीवन राय ने बी.पी.ई. के निर्देशों को उखाड़ फेंकते हुए सफल इस्पात समझौते की बात बताई. ठेका मजदूरों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इन्हें नौकरी में स्थायी बनाने के लिए राष्ट्रीय पैमाने पर संघर्ष का निर्माण करना पड़ेगा. बढ़ते हुए कम्पूट्राइजेशन के कारण नौकरी की सुरक्षा पर जो खतरा आ रहा है उसके लिए भी देशव्यापी संघर्ष करने की बात उन्होंने बताई.

रोबीन मुखर्जी (प. बंगाल) ने बताया कि प. बंगाल में तालाबंदियों व क्लोजर से 80 हजार से भी अधिक मजदूर प्रभावित हैं. इनका सुझाव था कि मिलबंदी के मामले में अन्य अप्रभावित मजदूरों को हड़ताल सहित अन्य संघर्षों के माध्यम से एकजुटता का इजहार करने के लिए लामबंद किया जाना चाहिये. इस सिलसिले में उन्होंने मेटल वाक्स का मिशाल दिखाया जहां एक इकाई में बंदी के विरोध में अन्य दो इकाईयों के मजदूरों ने हड़ताल किया. उन्होंने बताया कि प. बंगाल सरकार के लिए सारे बंद व बीमार इकाईयों को अधिग्रहण करना मुमकिन नहीं इसलिए तालाबंदियों व क्लोजर के खिलाफ देशव्यापी आन्दोलन का निर्माण किया जाना चाहिए.

हरिसाधन मित्रा (प. बंगाल) ने अमरीकी साम्राज्यवाद के युद्ध साजिशों के खिलाफ प. बंगाल में हो रहे आम सभाओं प्रदर्शनों आदि. के बारे में बिस्तार से बताया. 1. सितंबर को शांति के पक्ष में हुए विशाल प्रदर्शन तथा 20 दिसम्बर को होने वाली एक और शांति प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति की यह मांग है कि अमरीकी साजिशों के खिलाफ निरंतर संघर्ष जारी रखना होगा. तालाबंदी क्लोजर व औद्योगिक रूग्णता के बढ़ते घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों के पास इसे रोक पाने की क्षमता बहुत सीमित है इस लिए यह जरूरी है कि संयुक्त संघर्ष के जरिए इन सवालों पर मजदूरों की चेतना को बढ़ाया जाय. प. बंगाल में इन सवालों पर संयुक्त संघर्ष का निर्माण किया जा रहा है और 28 सितम्बर को सफल बंगाल बंद भी किया गया, उन्होंने जूट तथा इंजीनियरिंग उद्योग में हो रहे संयुक्त संघर्षों का जिक्र करते हुए बताया कि खदान क्षेत्रों में सी आई एस एफ की ज्यादतियों के खिलाफ सीटू यूनियनों द्वारा संयुक्त आंदोलनों को और तेज करना होगा.

वी. पी. चितन (तमिल नाडु) ने सीटू के अगुआई में राज्य में चलाए जा रहे संयुक्त संघर्षों का ब्योरा देते हुए बताया कि विभिन्न उद्योगों में तालाबंदी व क्लोजर के खिलाफ मद्रास में आम हड़ताल भी किया गया. मंदी, पैसों की हेराफेरी, सरकार की आयात नीति आदि सभी क्लोजर के मुख्य कारण है. उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ रास्ता रोको पिकेटिंग, गिरफ्तारी देना आदि विभिन्न तरीकों से संघर्ष चलाया जा रहा है जिसमें किसान व खेतिहर मजदूर भी शिरकत कर रहे हैं. पंडिचेरी में भी इस तरह के संघर्ष चलाया जा रहा है जिसमें तमाम तबके के मजदूर एक मंच पर लामबंद हो रहे हैं. ट्रांस्पोर्ट उद्योग में संघर्ष, कपड़ा उद्योग में बोनस के लिए संघर्ष आदि का जिक्र करते हुए उन्होंने राज्य कमेटी तथा सम्बद्ध यूनियनों द्वारा कामगार महिलाओं को संघर्ष में शामिल करने के लिए की जा रही प्रयासों के बारे में बताया.

वी. पी. चेरियन (केरल) ने केरल में हो रहे विभिन्न संघर्षों तथा खास कर बिजली मजदूरों की हड़ताल के बारे बताया. सरकार की आयात नीतियों तथा बिजली में कटौती तालाबंदियां वले- आफ के मुख्य कारण बताते हुए उन्होंने तालाबंदियों व क्लोजर के खिलाफ आम हड़ताल किए जाने का सुझाव दिया.

एन पदम्लोचन (केरल) ने सीटू तथा वाम जनवादी मोर्चे द्वारा राज्य में चलाए जा रहे संघर्षों का जिक्र किया तथा काजू, नारियल, जूट एवं हथ करघा उद्योगों में संकट और छोटे उद्योगों में तालाबदियों के समस्याओं के बारे में बताया. इन्होंने भी मालिकान तथा सरकार द्वारा अपनाई जा रही समाज बिरोधी रूख का लोगों में प्रचार करते हुए एक देश व्यापी संघर्ष छेड़ने के लिए सुझाव दिया. सीटू की सदस्यता का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सीटू के बढ़ते प्रभाव का सही प्रतिफलन नहीं हो रहा है. उन्होंने आग्रह किया कि बढ़ते चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए यूनियनों को और संगठित होना जरूरी है.

ज्योति बसु का भाषण

सीटू के उपाध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा कि विकास के पूंजीवादी रास्ता अपनाए जाने के कारण देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है इसकी ओर हमें तमाम मजदूरवर्ग की चेतना को केन्द्रित करना होगा इसलिए इस बुर्जुवा-सामंति राज में कोई वाम मोर्चा सरकार मजदूरों के न्यूनतम सुख सुविधाओं का भी ख्याल नहीं रख सकती है. केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूरों के एकजुट संघर्ष के जरिए ही ये अपनी मांगें हासिल कर सकती है. केन्द्र सरकार द्वारा वाम मोर्चा सरकार के प्रति अपनाई जा

रही विभेदकारी रुख का जिक्र करते हुए उन्होने बताया कि यही कारण है कि वे तालाबंदियों, क्लोजर व औद्योगिक रूग्णता की संख्या प. बंगाल में सबसे ज्यादा है. औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के मामलों में भी षड्यत्र की जा रही है जैसा कि हम राज्य में बैठाए जानेवाली इलेक्ट्रोनिक उद्योग तथा पेट्रो-केमिकल कॉम्प्लेक्स के मामले में देखते हैं. राज्य में 36 लाख रजिस्टर सुदा बेरोजगार हैं. जूट उद्योग में ही तालाबंदियों तथा मिलबंदी से पचास हजार मजदूर प्रभावित हैं. मजदूरों तथा जूट उत्पादकों के शोषण करके सिर्फ पांच:/छः परिवार बेतहाशा मुनाफा लूट रहे हैं और सरकार इन्हें संरक्षण दे रही तथा इस उद्योग को राष्ट्रीयकरण करने से इंकार कर रही है. बंद इकाइयों को सरकार न तो खुद अधिग्रहण कर रही है और नहीं राज्यों को वित्तिय सहायता देकर ऐसा करने दे रही है. फिर भी अपने सिमित साधनों के सहारे राज्य सरकार ने 13- बंद इकाइयों की अधिग्रहित की है पर इसे कारगर रूप से चलाने के लिए आधुनिकीकरण की जरूरत है जिसके लिए पैसे नहीं हैं. इसलिए वाम मोर्चे वाली सरकार की स्थापना के समय से ही, विभिन्न विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए राज्यों को अधिक क्षमता दिए जाने की मांग हम करते आ रहे हैं. यह सच है कि राज्य में सीटू की प्रतिष्ठा बढ़ी है पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संघटित होना अभी बाकी है जिसके कारण स्वास्थ्य सेवा में एस यू सी आई, कांग्रेस (आई) तथा नक्सलवादियों ने राजनीतिक रूप मे एक साजिशपूर्ण आंदोलन के चलते बच्चों सहित कई रोगियों को जीवन देना पड़ा.

शांति के लिए संघर्ष के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, हमें अपनी दुश्मन को, अमरीकी साम्राज्यवादियों को पहचानना होगा. इंदिरा गांधी कभी भी अमरीका का नाम नहीं लेगी वह लोगों को 'दो महाशक्तियों की बात कहकर भ्रमित करती रहेगी. मजदूर वर्ग को ही इस काम को पूरा करनाहोगा तथा शांति के लिए संघर्ष को रीगन प्रशासन के युद्ध साजिशों के खिलाफ खड़ा करना होगा. इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि प. बंगाल में 20 दिसम्बर को एक और विशाल शांति रैली का आयोजन किया जा रहा है.

मंगतराम पासला (पंजाब) ने सीटू द्वारा तालाबंदियों व क्लोजर तथा छंटनी के खिलाफ हो रहे संघर्षों का ब्यौरा देते हुए बताया कि 27 नवम्बर को पंजाब में हुए कन्वेन्शन में इसके खिलाफ संयुक्त आन्दोलन किए जाने पर जोर दिया गया. कन्वेन्शन में 2,500 प्रतिनिधियों में 1,800 सीटू से थे. यद्यपि संयुक्त आन्दोलन के लिए अन्य ट्रेड यूनियनों की दिलचस्पी उत्साहजनक नहीं है फिरभी सीटू की तरफ से इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है.

एस. एन. सोलंकी (हरियाणा) ने मालिकान तथा सरकार की मिलीभगत में पुलिस तथा गुण्डों द्वारा मजदूरों पर चलाये जा रहे बर्बर अत्याचार की बात बताते हुए कहा कि तालाबंदियों व क्लोजर के खिलाफ आवाज उठाने वाले मजदूरों को उनके घरों से, कार्यस्थलों से, निकालकर पीटा जा रहा है. उन्होंने पानीपत, सोनीपत, हिसार तथा अन्य जगहों का उदाहरण देते हुए बताया कि कई संसद सदस्यों तथा सीटू नेताओं द्वारा इन स्थानों का दौरा किये जाने के बावजूद यह बर्बर दमन और अत्याचार जारी है. पुलिस द्वारा साम्प्रदायिकता की आग भड़काई जा रही है. इन सारे हमलों के बावजूद सीटू के नेतृत्व में मजदूरवर्ग अपनी बहादुराना संघर्ष जारी रखा है. हिसार टेक्सटाइल मिल्स् में 2,000 मजदूरों के छंटनी के खिलाफ 16 नवम्बर से हड़ताल जारी है. उन्होंने, तालाबंदियों के खिलाफ गिरफ्तारी दिये जाने का समर्थन करते हुए सुझाव दिया कि इसे दिल्ली में होना चाहिए. अन्य यूनियनों द्वारा असहयोग किए जाने के बावजूद युद्ध के खिलाफ शांति संघर्ष के लिए सीटू द्वारा रैलियों का कार्यक्रम लिया गया पर राज्य सरकार ने इसकी सहमति नहीं दी.

एन. प्रसाद (आंध्र प्रदेश) ने सीटू द्वारा अकेले या अन्य ट्रेड यूनियनों के सहयोग से राज्य में हो रहे विभिन्न आन्दोलनों तथा हड़तालों के बारे में बताया. राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल, शिपयार्ड मजदूरों का संघर्ष, क्लोजर के खिलाफ 6,000 आई एल टी डी मजदूरों के आन्दोलनों आदि का जिक्र किया और न्यूनतम वेतन तथा कामगार महिलाओं के राज्य-स्तरीय सम्मेलन के बारे में बताया. 16 जनवरी से जूट उद्योग में हो रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल में शिरकत के लिए सीटू द्वारा मजदूरों को लामबन्द किए जाने की भी बात उन्होंने बताई. उनका कहना था कि '1 सितम्बर' राज्य के 60 स्थानों पर मनाया गया जिसमें पिछले साल से बहुत अधिक लोगों ने शिरकत की.

प्रस्तावें

महासचिव की रिपोर्ट पर बहस के बाद, प्रस्तावों को लिया युद्ध के खतरे तथा शांति के पक्ष में संघर्ष पर प्रस्ताव पेश करते हुए पी. राममूर्ती ने सभी राज्यों में 20 दिसम्बर से 28 दिसम्बर तक 'शांति सप्ताह' मनाने का सुझाव दिया. सर्व-सम्मति से पारित इस प्रस्ताव को ई. बालानंदन ने समर्थन किया.

श्रीलंका पर प्रस्ताव आर. उमानाथ ने पेश किया जिसका समर्थन शिवाजी पट्टनायक ने किया.

असम (रिलीफ आडरटेकिंग) बिल को अमल गोषदस्तिदार ने पेश किया और एन. पद्मलोचन ने समर्थन किया.

बिमल रणदिवे ने कामगार महिलाओं पर प्रस्ताव पेश किया जिसे चण्डी प्रसाद ने समर्थन किया.

क्लोजर तथा औद्योगिक रूग्णता पर प्रस्ताव को समर मुखर्जी ने पेश किया तथा के. रमानी ने समर्थन किया.

मोहम्मद अमीन ने जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण पर प्रस्ताव पेश किया जिसे हरसहाय सिंह ने समर्थन किया.

कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीकरण पर प्रस्ताव के. रमानी ने पेश किया जिसका समर्थन चित्तव्रत मजुमदार ने किया.

कुछ प्रस्तावों पर प्रस्ताव उप-समिति द्वारा लाई गई संशोधन को सभा ने मान लिया. ज्योति बसु के सुझाव के अनुसार यह तय किया गया कि बंगला देश पर, प्रस्ताव उप-समिति द्वारा एक प्रस्ताव का मसविदा तैयार किया जायेगा जिसे एवं अन्य बहुत से प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए सेक्रेटेरियट को अधिकार दिया गया. (पारित प्रस्तावों को इसी संख्या में छापी गई है).

क्रेडेंशियल कमेटी की रिपोर्ट

परसा सत्यनारायण ने क्रेडेंशल कमेटी की रिपोर्ट पेश की. सम्बद्धता के लिए 68 आवेदन पत्र मिले जिनकी कुल सदस्य-संख्या 17,067 है. इस कमेटी के सुझाव के मुताबिक 52 यूनियनों (कुल सदस्य-संख्या 13,848) की सम्बद्धता की बैठक ने मान्यता दे दी जबकि 16 यूनियनों (कुल सदस्य-संख्या 3,219) की सम्बद्धता को पूरे कागजात दाखिल किए जाने तक अनिर्णित रखा गया.

सभी यूनियनों को अपनी सम्बद्धता तथा अन्य कागजातों को ठीक-ठीक रखने के लिए कहा गया ताकि सीटू की सदस्यता का सही प्रतिफलन हो सके तथा संगठन को सभी तरह से शक्तिशाली बनाया जा सके.

समर मुखर्जी द्वारा जवाब

महा-सचिव की रिपोर्ट पर बहस का जवाब देते हुए समर मुखर्जी ने मजदूर-वर्ग को शांति के लिए लगातार संघर्ष का निर्माण करने के आह्वान पर जोर दिया और बताया कि मजदूर-वर्ग की चेतना को बढ़ाना होगा ताकि वह मुख्य युद्ध-विरोधी शक्ति के रूप में अपने आप को उभार कर साम्राज्य-वादी युद्ध-साजिशों को शिकस्त देने की अपनी अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभा सके. कांग्रेस सरकार द्वारा विकास के पूँजीवादी रास्ता पर चलने का परिणाम के बारे में मजदूर-वर्ग को समझना होगा. आई एम एफ की शर्मनाक शर्तों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप मजदूर-वर्ग के लिए स्थिति और भी गम्भीर हो रही है. आने वाले दिनों में तालाबंदी, मिलबंदी तथा औद्योगिक रूग्णता की घटनाएं और भी भयंकर खतरा पैदा कर देगी. इसलिए यह लाजिमी है कि इन चुनौतियों के मुकाबले के लिए ट्रेड यूनियन एकता को बढ़ाते हुए सरकार की नीतियों को बदलने के लिए नये तरीकों से संघर्ष का निर्माण करें.

इन परिस्थितियों में संघर्ष को सफल बनाने के लिए संगठन को और भी शक्तिशाली करना होगा. एक तरफ जैसे सीटू की सदस्यता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास जारी रखना होगा, दूसरी तरफ संगठन के सभी स्तर पर कार्यविधी के जनवादी तौर-तरीके कायम करना होगा. उन्होंने राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों से तालाबन्दी व क्लोजर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए आह्वान किया जिससे कि 20 जनवरी को दिल्ली में होने वाली कन्वेन्शन को सफल बनाया जा सके और उसके बाद देशव्यापी संयुक्त संघर्ष संगठित किया जा सके.

बी टी आर का समापन भाषण

बैठक को सफलता के साथ आयोजित करने के लिए बी. टी. आर ने बिहार राज्य कमेटी तथा वालंटियरों को बधाई दी.

उन्होंने बताया कि देश आज एक गम्भीर आर्थिक संकट से गुजर रही है— विकास की पूंजीवादी रस्तों पर चलने का यह नतीजा है. पर हम शायद अभी भी इसे नजर अंदाज कर रहे है. इस संकट के कारण सभी तबके मेहनतकश लोग तबाह हो रहे हैं. तालाबंदी व क्लोजर की घटनाएं बेरोजगारों की कतार को और लम्बी बना रही है. इसके साथ साथ अनियंत्रित रूप ले सामानों की कीमतों में बृद्धि ने हर परिवार के लिए एक असहनीय बोझ बन रही है और मजदूर तथा जनता के सामने पूंजीवाद एक अभिशाप के रूप सामने आ रही है. पर भारत सरकार अपनी नेतृत्ववादी प्रचारों से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में लगी हुई है. पर मजदूर वर्ग को कम्युनिष्ट मैनीफेस्टों की शिक्षा को ग्रहण करना होगा कि इस संकट से तथा शासक वर्ग से लड़ने का असल फल संगठन के बढ़ते शक्ति में ही समाया हुआ है. अगर हम बाम मोर्चा सरकार से इस संकट को खत्म करने का उम्मीद करेंगे तो ये सुधारवादी विचार होगी. नौकरी की इस संकटपूर्ण स्थिति में सीटू को एक चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ेगा तथा वाम मोर्चा सरकारों की समर्थन लेकर शासक वर्ग के खिलाफ संघर्ष को और भी तीव्र करना होगा. मजदूरवर्ग के पास ताकत है वक्त का तकाजा सिर्फ ट्रेड यूनियन एकता की है जिसे कायम करने के लिए सीटू को एक चालक शक्ति के रूप मे उभरना होगा ताकि इस इजारेदार परस्त, जमींदार परस्त, बहुराष्ट्रीय निगम परस्त सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष को और व्यापक रूप से आगे बढ़ाया

(शेष पृष्ठ 31 पर)

महासचिव की रिपोर्ट

(संक्षेप्त रूप)

—समर मुखर्जी

साथी सभापति और साथियों,

कानपुर के पांचवें सम्मेलन के बाद, हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भी गम्भीर हो गई है. साथ ही साथ, मजदूर-वर्ग का आन्दोलन, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों पैमाने पर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है. हमें इसका जायजा लेते हुए अपनी गतिविधियों के कार्यक्रम को तय करना होगा. यह कार्यक्रम, सिर्फ परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ही नहीं बल्कि भारतीय मजदूरवर्ग को उन पर सौंपी गई ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से भी ली जायेंगी.

बढ़ते युद्ध के खतरे

हमारे अध्यक्ष का. बी.टी. रणदिवे ने नाभिकीय विनाश के बढ़ते खतरे के बारे में, समूची दुनिया में शांति-संघर्षों के बढ़ते ज्वार के बारे में; युद्धोन्मादि रीगन प्रशासन के अड़ियल रवैये के बारे में तथा सोवियत संघ व समाजवादी राष्ट्रों की शांति प्रचेष्टाओं के बारे में विस्तार से बताया है. सोवियत संघ तथा पूर्वी योरोपीय देशों, जिन्हें पशिंग-II तथा क्रूइस जैसे द्रुत गति मिसाइलों का निशाना बनाया गया है, विश्व शांति के लिए दुनिया को लामबंद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. पिछले छः महीनों में हुए चार अन्तर्राष्ट्रीय शांति सभाएं जिनमें सीटू ने भी शिरकत की, इन प्रचेष्टाओं के द्योतक हैं. इसके अलावा भी कई औद्योगिक बैठकें हुई जिसमें मुख्य रूप से शांति के सवाल पर ही विचार-विमर्श हुए, क्योंकि विश्व के शांतिप्रिय लोगों के सामने मानव समाज के सिर पर मंडराते इस विनाशकारी नाभिकीय युद्ध को रोकने के सिवाय और कोई अहम सवाल हो नहीं सकता.

डब्ल्यू एफ टी यू के आह्वान पर, सीटू, एटक, यू टी यू सी, टी यू सी सी तथा इंटक (दारा) ने संयुक्त रूप से इस बर्ष 1 सितम्बर को शांति तथा एकजुटता दिवस के रूप में मनाया. पिछले सालों से इस साल इसे और व्यापक रूप से मनाया गया.

युद्ध के खतरे के बारे में, हर मंच और हर मौके पर मजदूर-वर्ग को हम सचेत कर रहे हैं. कलकत्ता, दिल्ली एवं अन्य स्थानों में ग्रेनाडा पर अमरीका के शर्मनाक हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुई. फिरभी, हम यह मानते हैं कि इन राजनीतिक घटनाओं के विरोध में हमारी प्रतिक्रिया उतना तीव्र नहीं हो सका जितना कि होना चाहिए था. तमाम मेहनतकश लोगों को लामबन्द कर एक शक्तिशाली शांति आन्दोलन में शामिल करने के लिए कानपुर द्वारा दिए गए निर्देशों को हम पूरा नहीं कर पाये.

इंटक के एन.के. भाट तथा एच एम एस के बी.एम. तूफान को, जिन्होंने सोफिया सम्मेलन में भाग लिया था, हमने यह प्रस्ताव दिया था कि नाभिकीय युद्ध के खिलाफ हमारे देश में एक प्रतिरोध आन्दोलन का निर्माण करना चाहिए. हम इस मौके पर एक बार फिर इंटक तथा एच एम एस सहित सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से यह अपील करते हैं कि देश में एक शक्तिशाली शांति आन्दोलन का निर्माण करें. हमें विश्वास है कि इसे आप सिर्फ सहमति नहीं देंगे बल्कि इसे कारगर रूप देने के लिए राज्य स्तर पर शांति-मार्चों का आयोजन करने में पहल-कदमी दिखायेंगे क्योंकि स्थिति दिन ब दिन गम्भीर होती जा रही है.

भारतीय अर्थनीति के गहराते संकट

तेजी से बिगड़ती देश की आर्थिक स्थिति पर का. बी.टी. आर ने विस्तार से आलोचना की है. मैं सिर्फ महंगाई की स्थिति पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा जिससे आप आर्थिक परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं.

औद्योगिक मजदूरों के औसत मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) के अनुसार—

मासिक/सालाना औसत	आम सूचकांक	वार्षिक वृद्धि	खाद्य सूचकांक	वार्षिक वृद्धि	दोनों के बीच अंतर
जनवरी 1980	371	—	384	—	13
1980	390	19	406	22	16
1981	441	51	465	59	24
1982	475	34	498	33	23
1983	541	66	578	80	37
जनवरी 1980 से जुलाई 1983 तक प्रतिशत वृद्धि	45.8%		50.5%		

महंगाई पर रोक लगाने की वित्तमंत्री जो लम्बी बातें कर रहे हैं उसके विपरीत हमारे देश के मजदूर वर्ग को आज दो अंकों वाली महंगाई का सामना करना पड़ रहा है. गौर करने लायक दूसरी बात यह है कि 1982 को छोड़कर खाद्य

सामग्रियों का सूचकांक अन्य सामानों से ज्यादा तेजी से बढ़ा है. आम सूचकांक सितंबर 83 में 554 पर पहुंच चुका है जिसका मतलब है 50 फीसदी की वृद्धि — हर तबके के मजदूरों के असल वेतन किस तरह खा रही है इसका अंदाजा मिल सकता है.

महंगाई और भी बढ़ेगी. अखबारों में छपी रिपोर्टों के अनुसार कोयला, रेल यातायात, माल भाड़ा आदि में वृद्धि अनिवार्य हैं. आम जनता को गुमराह करने के लिए सरकार वेतन में बढ़ोत्तरी इसका कारण बताएगी. इसलिए अभी से ही आमतौर से ट्रेड यूनियनों को और खासकर सीटू यूनियनों को अभियान चलाकर लोगों को यह बताना होगा कि वर्त्तमान वेतन में बढ़ोत्तरी, मूल्य वृद्धि के कारण ही हुआ. दरअसल महंगाई जहां 50 फीसदी से बढ़ी है वहां वेतनों में वृद्धि की हार सिर्फ 14 से 28 फीसदी है जिसका मतलब है मजदूर, महंगाई के प्रभाव को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए और इस तरह उनकी असली वेतन घट रही है. और अगर सार्वजनिक क्षेत्र में महंगाई भत्ता त्रिपक्षीय समिति में हो रहे वार्त्ताओं द्वारा मजदूर महंगाई के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने की अपनी मांग को हासिल नहीं कर पाए तो उनके असल वेतन में और भी कमी आएगी क्योंकि कीमतें और भी बढ़ेंगी. महंगाई के खिलाफ अभियान को बर्बाद जन वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने की मांग के साथ जोड़ना होगा क्योंकि महंगाई से सभी प्रभावित है. इसलिए अनिवार्य वस्तुओं को कीमतों का नियंत्रण करने तथा सार्वजनिक वितरण को कारगार बनाने के लिए खाद्यान्न व रोजमर्रा की अन्य आवश्यकताओं के थोक व्यापार का अधिग्रहण-अगस्त '83 में हुई राष्ट्रीय कन्वेन्शन के इस नारे को हमें लोकप्रिय बनाना होगा.

गौरतलब है कि सरकार 1960 सूचकांक में, 7 प्वाइंटों की सुधार लाने की रथ कमेटी की सर्वसम्मति सिफारिशों को मानने से यह कहकर इंकार कर रही है कि एक नए सूचकांक को लागू करने की सील कमेटी के सिफारिशों पर कारगर कदम उठाए जा चूके हैं. मूल्य सूचकांक से जुड़े हुए परिवर्त्तनशील महंगाई भत्ता पाने वाले मजदूर 9.10 रू प्रतिमाह के दर से कम पा रहे हैं, जिसका फायदा मालिकान को प्राप्त हो रहा है.

फरवरी 9, 1983 को सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल संगठन (योजना मंत्रालय) द्वारा जारी 1981-82 वित्त वर्ष के आंकड़ों के अनुसार 1981-82 वर्ष में राष्ट्रीय आय में 1980-81 के 8.1 फीसदी के उपर और 5 फीसदी की वृद्धि हुई है तथा इसी अवधि में प्रति व्यक्ति की आय में 2.8 फीसदी की वृद्धि हुई है.

बढ़ती हुई महंगाई, मजदूरों को कम पैसे दिए जाना या उनके असल वेतनों में कमी एवं इसी अवधि में राष्ट्रीय आय में वृद्धि इस बात की ओर इशारा करती है कि पूंजीपति—सामंति शोषक वर्ग मजदूरों के श्रम से सबसे ज्यादा फायदा उठाया एवं पिछले सात सालों में बीस बड़े इजारेदार घरानों ने अपने सम्पत्ति को दुगना बना लिया.

बढ़ते संघर्ष

कानपुर सम्मेलन और इस कार्यकारिणी की बैठक के बीच के अवधि में संघर्ष के बढ़ते ज्वार में सिर्फ मजदूर वर्ग ही नहीं बल्कि हर तबके के जनवादी लोग लामबंद हो रहे है. इन संघर्षों को हमें किसान आंदोलनों तथा बढ़ते जनवादी आंदोलनों के पृष्ठ भूमि में विचार करना होगा. यद्यपि मजदूर-वर्ग ने इन आंदोलनों में शिरकत की, पर यह नहीं कहा जा सकता है कि इन आंदोलनों को नेतृत्व दिया. हमारे इस खामी को नोट करना होगा.

और यह भी सच है कि यह सारे संघर्ष या तो बढ़ते हमले को रोकने के लिए या वेतन में कमी के खिलाफ हुए जिसे हम प्रतिरोध संघर्ष समझते हैं. सरकार की जन विरोधी तथा मजदूर बिरोधी नीतियों को बदलने के लिए संघर्ष का निर्माण अभी बाकी है. बहरहाल तमाम तबके के मेहनत कश लोगों के बढ़ते संघर्ष का हम स्वागत करते हैं.

इन सारी घटना-विकास से यह बात सामने आ रही है कि महंगाई, क्लोजर, तालाबन्दी, छंटनी आदि के खिलाफ मेहनतकश लोग अपना रोष प्रकट करते हुए संघर्ष के रास्ते पर आ रहे हैं. वाम तथा अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा समर्थन दिए जाने के फैसले से, आनेवाले दिनों में संघर्ष तीव्र से तीव्रतर होता जायेगा और सीटू को इस मौके पर पहलकदमी दिखाकर तमाम मजदूर-वर्ग को एकजुट करते हुए जनवादी लोगों के और व्यापक हिस्से को लामबंद करना होगा, जिससे, हो रहे इस भारी शोषण के खिलाफ एक शक्तिशाली ताकत का निर्माण किया जा सके.

अत्याचार

यह नोट किया जाना लाजिमी है कि पुलिस तथा मालिकान के गुंडों द्वारा चलाये गए बर्बर दमन और अत्याचारों को झेलते हुए इन बहादुराना संघर्षों को चलाया गया है. असम के हमारे साथियों ने कातिलाना हमले, आगजनी, लूट और हिंसक घटनाओं के बावजूद अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया. विशाखा-पट्टनम् स्टील प्लांट में हड़ताली ठेका मजदूरों पर पुलिस द्वारा गोली चलाकर मजदूरों की हत्या किया जाना, कांदला 'मुक्त व्यापार क्षेत्र' में 13 सितम्बर के गोलीकांड आदि प्रबन्धकों के इन उकसावेपूर्ण हत्यारे मुहिम की हम कड़ी भर्त्सना करते हैं. सरकार तथा मालिकाना की मिलीभगत में समझौतों तथा कानूनों का नंगे रूप से उल्लंघन किया जा रहा है और मजदूरों की जानें ली जा रही हैं.

निर्यात बढ़ाने के नाम से मालिकवर्ग सरकार की मदद से मजदूरों को 'बंधुवा मजदूर' में परिणत कर रहे हैं और विरोध करने वाले मजदूरों की या तो पिटाई की जाती है या उन्हें खत्म कर दिया जाता है. गैर-कानूनी छंटनी के खिलाफ संघर्षरत जे. के. सिंथेटिक्स् कोटा के मजदूरों पर बर्बर पुलिस दमन का भी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं. त्रिपुरा के श्रममन्त्री तथा हमारे कार्यकारिणी के सदस्य बिरेन दत्ता के इस छंटनी के विरोध में दिये गये पत्र के जबाब में राजस्थान सरकार ने इस छंटनी को गैर-कानूनी स्वीकार करने के बावजूद सिंहानियाओं के सेवा के लिए राज्य के तमाम दमन तंत्र को छोड़ रखा है जिनके इशारे पर मजदूरों को गिरफ्तार कर या तो उनसे जबरन काम कराया गया है या उन्हें जेल भेजा गया. उनके परिवारवाले तथा बच्चों को भी इस बर्बर अत्याचार का शिकार बनाया गया. का. मोहम्मद इसमाईल, का. बासुदेव आचार्या तथा का. सइफूद्दीन चौधरी, सभी सांसदों ने कोटा का दौरा करने के बाद यह बताया था कि वहां आतंक राज जारी है जहां हर मौलिक अधिकारों को कुछ दिनों के लिए दफना दिया गया था. सीटू कोषाध्यक्ष का. ई. बालानन्दन ने इस सिलसिले में आई एल ओ को तार एवं बाद में रिपोर्ट भेजा जिसे केस नं. 1227 के रूप में दर्ज किया गया है.

कोटा संघर्ष की महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहां काम कर रहे मजदूरों ने अपने छंटे हुए साथियों को काम पर वापस लिए जाने के मांग पर इतनी लम्बी लड़ाई लड़ी. और दमनात्मक कार्रवाईयों की खास बात यह है कि मजदूर वर्ग आन्दोलन के खिलाफ मालिकान द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल का इस्तेमाल किया जाना. पानीपत—एन एफ एल में ये लोग गुप्तचर अधिकारी के रूप में काम किए जिसके खिलाफ मजदूरों ने अपना रोष प्रकट किया और बाद में हुई झड़प में मजदूरों को बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई. ई सी एल में सी आई एस एफ तो विजयी सेना के रूप में कोयला मजदूरों पर अत्याचार चला रखा है. सुरक्षाबल का काम है सम्पत्ति की रक्षा करना न कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन में हस्तक्षेप करना. सुरक्षाबल को इस तरह इस्तेमाल करने का मजदूर आन्दोलन द्वारा एकजुट रूप से विरोध किया जाना चाहिए.

सीटू सक्रिय सदस्यों पर हमले

बड़े दुख के साथ आपके समक्ष, सीटू सक्रिय सदस्यों एवं उनके परिवारों पर हो रहे कातिलाना हमले के बारे में रिपोर्ट में रखना पड़ रहा है. पहले भी हमने मालिकान के संरक्षण में प्रतिस्पर्द्धी यूनियनों के समाज-विरोधी पिछलग्गुओं द्वारा हमारे सक्रिय सदस्यों पर कातिलाना हमले किए जाने की बात कही थी पर अब स्थिति इस हद तक आ गई है कि सीटू कार्यकर्त्ताओं के न मिलने पर उनके परिवार तथा बच्चों को भी निर्ममता से हत्या की जा रही है. मोदीनगर में, 9 जुलाई, 1983 को एच एम एस यूनियन के सदस्यों ने पांच व्यक्तियों की हत्या कर दी जिनमें से सिर्फ दो सीटू से सम्बंधित थे अन्य तीन उनके परिवार के सदस्य थे.

1 जुलाई, 1983 को अशोक लेलैंड, होसुर के सीटू यूनियन नेता का. शक्तिमेल की हत्या, प्रतिस्पर्द्धी यूनियन के एक सदस्य द्वारा की गई.

24 सितम्बर को कलता खदान में उड़ीसा सीटू राज्य कमेटी के सदस्य का. अनंत राउत के परिवारवालों पर संघी गुंडों ने कातिलाना हमले किए तथा उनके पांच वर्षीय पुत्र संजय की बर्बरता से हत्या कर दी और उनकी पत्नी एवं पत्नी की बहन को गम्भीर रूप से घायल किया. हमारे देश के ट्रेड यूनियन आन्दोलन की यह एक खतरनाक रुझान है. ट्रेड यूनियन कार्य-कर्त्ताओं एवं उनके परिवारों और रिस्तेदारों पर किए जा रहे इन बर्बर तथा जघन्य हत्याओं की भर्त्सना करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है. मजदूरों को अपने पसंद की यूनियन चुनने की या बनाने का सम्पूर्ण अधिकार है इसका मतलब यह नहीं कि उनकी हत्या कर दी जाय और जहां तक परिवारवालों की हत्या का सवाल है सभी को उनकी भर्त्सना करनी चाहिए. हम इन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजली अर्पित करते हैं और उनके शोक-संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते है.

एक जुट कार्यवाही

एक जुट संघर्षों के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में संघर्ष की मुख्यधारा में किसानों को शामिल करने तथा देश के पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को शामिल करने का हमारा जो दृष्टिकोण है वह धीरे धीरे फैल रही है. कई जगहों पर स्थानीय रूप से या जिलास्तर पर, अत्याचारों के खिलाफ या अन्य संघर्षों में इस एकजुटता का प्रतिफलन हम देखते जरूर हैं पर इसे और व्यापक बनाना होगा. इस एकजुट संघर्ष से ही हम वर्ग चेतना तथा वर्गीय दृष्टिकोण को बढ़ा सकते हैं जिसके बिना पृथकतावादी ताकतों को शिकस्त देना या मजदूरवर्ग को वर्ग के आधार पर एकबद्ध करना सम्भव नहीं.

संघर्षों को समीक्षा

आगे बताए गए ज्यादा से ज्यादा संघर्ष को अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त रूप से चलाया गया. एक जुट संघर्ष के आह्वान को अब मजदूरों के व्यापक हिस्सों को आकृष्ट कर रहा है और कुछ क्षेत्रों में तो इंटक भी साथ आ रही है. इससे हमें मजदूरों के और व्यापक हिस्से को एक बद्ध करने का तथा अपने संगठन के गतिविधियों को बढ़ाने का मौका मिल रहा है.

इसलिए यह जरूरी है कि स्वतंत्र रूप से या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से चलाए जा रहे संघर्षों का हम समीक्षा करें.

पृथकतावादी ताकतें

हमें पृथकतावादी ताकतों की चुनौतियों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना होगा. पंजाब की स्थिति बिगड़ती जा रही है जिसके कारण अखिल भारतीय पथ परिवहन कर्मचारी फेडरेशन के सम्मेलन को हमें स्थगित करना पड़ा. हैदराबाद में आर एस एस तथा जमायते इस्लामी द्वारा 9 सितंबर से साम्प्रदायिक दंगा भड़काई गई.

नवम्बर 1983 में 'एकात्मता यज्ञ' चलाकर विश्व हिन्दु परिषद ने (जो आर एस एस से सम्बध रखने की बात खुली तरह कहते हैं,) साम्प्रदायिकता का हौवा पैदा कर रही है. सीटू यूनियनों को इसके खिलाफ मजदूर वर्ग के बीच विचारात्मक अभियान को तीव्र करना होगा.

ट्रेड यूनियनों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन

इस बढ़ते संघर्ष के पृष्ठभूमि में ही ट्रेड यूनियनों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 21 अगस्त '1983 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ. क्लोजर, तालाबंदियों तथा छंटनी के कारण अशांत वातावरण, और इसके साथ अधिग्रहण तथा राष्ट्रीयकरण करने से इंकार करते हुए इसे पुराने मालिकान को सौंप देने की सरकार की रवैये के कारण अशांति और भी बढ़ती जा रही है. मजदूर वर्ग के सामने आज नौकरी की सुरक्षा तथा बेरोजगारी, महंगाई, ज्वलंत तात्कालिक समस्या बन गई है. इन्हीं कारणों के लिए यह सम्मेलन एक गहरा महत्व रखता है.

तालाबंदियों, क्लोजर, छंटनी तथा डिनोटिफिकेशन

सम्मेलन द्वारा अपनाई गई प्रस्तावों को अगर कारगर रूप दिया जाय तो भिन्न सवालों पर भिन्न कन्वेन्शनों का होना व्यापक कार्यक्रम का दिशासूचक है. जैसा कि तालाबंदियों व क्लोजर पर 20 जनवरी 1984 को नई दिल्ली में हो रहे विशेष कन्वेन्शन, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर फौरी कदम उठाना लाजिमी है.

पिछले दो सालों से भी उपर मजदूरवर्ग तथा ट्रेड यूनियन आंदोलनों की सरकार से यह मांग रही है कि जूट उद्योग तथा अन्य अधिग्रहित इकाइयों को राष्ट्रीयकरण की जाय पर सरकार ऐसा करने से इंकार कर रही है.

सितम्बर 1980 कन्नानोर जनरल काउंसिल के बाद से ही यह नोट किया गया था कि मजदूरों के बहादुराना संघर्षों को तोड़ने के नये हथियार के रूप में तालाबंदियों को इस्तेमाल करने की रुझान देखी जा रही है जिसके खिलाफ सीटू ने मजदूर-वर्ग को चेतावनी दी थी. 1982 तक यह देखा गया कि तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुए श्रम-दिवस हड़तालों से बहुत ही ज्यादा है और पश्चिम बंगाल में स्थिति सबसे गम्भीर रही जहां तालाबंदियों के कारण 85 फीसद श्रम-दिवस नष्ट हुए जिसके विपरीत हड़तालों से नष्ट हुए श्रम-दिवस सिर्फ 15 फीसद रही. प. बंगाल के जूट उद्योग में एक के बाद एक तालाबन्दी घोषित की गई जबकि उत्पादन में वृद्धि होती गई. जूट सेठों के इस भयानक हमले से मजदूरों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीयकरण की मांग की जा रही है.

यह याद रखने योग्य बात है कि बीमार उद्योगों के अधिग्रहण का सिलसिला 25वां राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के सर्व-सम्मत फैसले के कारण शुरू हुआ. इजारेदार घरानों ने इस फैसले का फायदा उठाकर फण्डों को अन्य ज्यादा मुनाफेवाले उद्योगों में लगाना शुरू किया तथा चालू उद्योगों को बीमार बनाकर राष्ट्रीय कोष पर बोझ लाद दिया. अधिग्रहित इकाईयों की हालत भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध के कारण और बदतर होती गई. सरकार द्वारा लागू की जा रही रिलीफ अन्डरटेकिंग बिलों के जरिए इन बोझों को मजदूरों के कंधों पर थोपा जा रहा है. उद्योगपतियों, खासकर इजारेदार घरानेवालों की मदद के लिए इन कानूनों के जरिए मजदूरों को सजा दी जा रही है. जब सरकार ने आई एम एफ के शर्तों के मुताबिक, पहले अधिग्रहित इकाईयों का राष्ट्रीयकरण करने से इंकार करने और फिर इन इकाईयों के पुराने मालिकान को वापस करने की साजिश बनाई तो स्थिति और भी बिगड़ गई.

हमें समझना होगा कि डिनोटिफिकेशन का मतलब है दिवालियापन क्योंकि आई आर सी आई, जिनपर इन इकाईयों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, के कुप्रबंध तथा ज्यादा से ज्यादा इकाईयों में पुराने प्रबंधकों को ही रहने देने के कारण इन मालिकों को हेरा-फेरी करने का पूरा मौका दिया गया. यह गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी है कि किसी इकाई को दिवालिया घोषित करने के पहले उसके मजदूर पक्ष की बात को भी सुनना पड़ेगा, जो नहीं किया जाता है. यद्यपि यह समस्या मुख्यतः राज्य सरकारों की है जिसे इसका बिकल्प कोई व्यवस्था या सुझाव देने का मौका मिलना चाहिए पर किसी राज्य सरकार से भी विचार-विमर्श नहीं किया गया. यह एक और कारण है जिसके लिए सीटू ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का पुनर्गठन की मांग की है.

कामगार महिलाएं

इसीतरह, कामगार महिलाओं की समस्याओं के बारे में भी हमें गम्भीरता से विचार करना होगा. कामगार महिलाओं को संगठित करने तथा उनकी मांगों के समर्थन में आवाज उठाने की हमारी प्रचेष्टाओं के फलस्वरूप अभियान समिति ने इस सवाल पर विशेष सम्मेलन बुलाने का फैसला किया है. अब

और व्यापक रूप से कामगार महिलाओं को ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल करने का प्रयास करना होगा.

उद्योगवार गतिविधियां

इस बीच विभिन्न उद्योगों में गतिविधियां बढ़ी हैं. पांचवें सम्मेलन के दौरान ही कई उद्योगभित्तिक बैठकें हुई. दूसरा राष्ट्रीय कन्वेन्शन के समय भी यह सिलसिला जारी रहा. मैं इस मौके पर सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को, खासकर कोयला उद्योग के मजदूरों का अभिनन्दन करता हूं, जिन्होंने अपने एकजुट संघर्ष से सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया तथा बी पी ई निर्देशों को उखाड़ फेंका. सार्वजनिक क्षेत्र में हमारी गतिविधियां बढ़ने के साथ-साथ मजदूरों पर हमारा प्रभाव भी बढ़ा.

मैं कोयला खदान मजदूरों का गर्मजोशी से अभिनन्दन करता हूं जिन्होंने अपने जीवनयापन की स्थिति के सुधार में एक जबर्दस्त संघर्ष के जरिए कामयाबी हासिल की है तथा कोयला मजदूरों के बीच काम कर रहे सारे ट्रेड यूनियनों को समझौते-वार्ताओं में प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिए संघर्ष किया. समझौता-वार्ताओं में सहमति के बावजूद इसे लागू किए जाने पर बी पी ई द्वारा गतिरोध पैदा किए जाने की साजिशों को इनके एकजुट प्रतिरोध ने शिकस्त दिया. पिछले समझौते के कुछ शर्तों को लागू न किए जाने की इनकी प्रचेष्टाओं को ध्यान में रखते हुए मजदूरों को इस बार सजग रहना पड़ेगा.

अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ की रिपोर्ट से यह देखा जा रहा है कि कोयला खदान मजदूरों पर भारी दमन जारी है. इनके जीवन की सुरक्षा की कोई गारण्टी नहीं, और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर उन्हें जबरदस्ती काम कराया जाता है. इसके अलावा इनके ट्रेड यूनियन आन्दोलनों को विभिन्न तरीकों से कुचला जा रहा है. सुरक्षाबल आदि के इस्तेमाल के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं. इन्हें सप्ताह में सातों दिन काम करवाया जा रहा है ताकि इन्हें एकजुट होने का मौका नहीं मिले. माइन्स एक्ट तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दिये गए आश्वासनों का उल्लंघन करते हुए यह सब किया जा रहा है.

मैं सुरक्षा बल तैनात किए जाने का कड़ी भर्त्सना करता हूं जिन्होंने तिरत में सीटू झंडे को जलाने की हिम्मत तक की ऐसा लगता है कि ट्रेड यूनियन तथा जनवादी आंदोलनों में पुलिस की हस्तक्षेप न करने देने की प. बंगाल वाम मोर्चे सरकार की नीति के कारण ही ई. सी. एल. प्रबंधकों को सी आई एस एफ को बुलाना पड़ा.

इन अत्याचारों से मजदूरों के बीच अशांति फैल रही है. कोटाडिह घटना के बाद मजदूरों ने हड़ताल का नोटिस दिया जिसे प्रबंधकों के झुकने पर ही वापस लिया गया. इन अत्याचारों को सीटू गम्भीरता से नोट करता है तथा कोयला उद्योग के तमाम यूनियनों को आंदोलन के जरिए इसे रोकने को आह्वान करता है. अगर कोयला उद्योगों के मजदूरों को बाध्य होकर हड़ताल करना पड़े तो सभी यूनियनों को इन कोयला मजदूरों के साथ एकजुटता का इजहार करने के लिए तैयार होना पड़ेगा.

प. बंगाल के बहादुर जूट मजदूरों जो 16 जनवरी 1984 से लगातार हड़ताल पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं. उनका हम अभिनंदन करते हैं. पिछले कई सालों से ये जूट सेठों के अत्याचारों के खिलाफ एकबद्ध होकर संघर्ष कर रहे हैं जबकि पिछले तीन सालों से सत्तर हजार से भी अधिक मजदूर ताला-बंदियों से प्रभावित हैं. जब इनके सारे प्रयास विफल हुए, जब कांग्रेस (आई) सरकार ने प. बंगाल विधान सभा के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सर्व सम्मत अपील पर भी अमल नहीं किया तो इन्हें मजबूर होकर यह फैसला लेना पड़ा. आप सबकी ओर से मैं इस संघर्ष में सम्पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन देता हूं तथा सभी सीटू यूनियनों का आह्वान करता हूं कि जूट उद्योग को राष्ट्रीयकरण किए जाने की मांग करते हुए केन्द्र सरकार के पास तार भेजे. मुझे विश्वास है, इस संघर्ष के साथ एकजुटता का इजहार करने के लिए हमारे राज्य कमेटियां जरूरी कार्रवाई करेगी.

इस्पात उद्योग में ठेका मजदूरों के सवाल को दृढ़ता से उठाने के लिए मैं स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया के साथियों को बधाई देता हूं. इन्होंने उन मजदूरों को संगठित करने तथा उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने में मदद किया है. जमशेदपुर के हमारे बहुत साथियों को ठेका मजदूरों के संघर्ष के साथ एक-जुटता दिलाने के कारण विक्टिमाइज किया गया है—हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी इस एकजुटता के परम्परा को आगे बढ़ाया जायगा.

हम नेशनल फर्टीलाइजर लि. पानीपत के मजदूरों को भी बधाई देते हैं जिन्होंने ठेका मजदूरों को काफी समर्थन दिया.

सभी उद्योगों में ठेका मजदूरों के प्रति बढ़ते रूझान को उन्हीं उद्योग के मजदूरों द्वारा ही खत्म करना सम्भव है और इस तरह संगठित तथा असंगठित मजदूरों के बीच के दरार को खत्म किया जा सकेगा.

सरकार की उदासीनता के बावजूद बंदरगाह मजदूरों खासकर गोदी मजदूरों द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं.

सीटू संगठन

साथियों, सीटू संगठन के सवाल पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा. मजदूर वर्ग के सवालों को आगे बढ़ाने

(शेष पृष्ठ 44 पर)

सीटू वर्किंग कमेटी द्वारा अपनाये गये प्रस्ताव

श्रीलंका पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर — 2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक पिछले जुलाई में श्रीलंकावासी तमिल अल्पसंख्यकों पर हुए बर्बर हिंसक हमलों की निन्दा करती है. इथनिक अल्पसंख्यकों की नरसंहार से सिर्फ भारत के मजदूर-वर्ग को ही नहीं बल्कि तमाम भारतवासियों को भी स्तम्भित कर दिया.

विकास की पूँजीवादी रास्ते पर चलने के कारण तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तों के प्रभाव से श्रीलंका की अर्थनीति, बढ़ते बेरोजगारी के साथ, संकटपूर्ण होता गया और यह स्थिति सिंहली बहुसंख्यकों को तमिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा करने की अमरीकी साम्राज्यवादी साजिशों के लिए मददगार साबित हुई. इससे श्रीलंका की अर्थनीति को और भी गहरी चोट पहुंची. सैकड़ों फैक्ट्रियां बर्बाद हुए जिससे सिंहलियों सहित एक लाख से भी ऊपर मजदूर बेरोजगार हुए.

यह बैठक, भारत के खिलाफ कुत्सा प्रचार करने की तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ हाथ मिलाकर गुट-निर्पेक्ष आन्दोलन के भावनाओं तथा उसके फैसले (जिसमें जयवर्द्धने खुद शामिल थे) के साथ विश्वासघात करने के लिए, श्रीलंका सरकार की भर्त्सना करता है. उनके साम्राज्यवाद परस्त साजिशों का पता तब चला जब उन्होंने श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी सहित तीन वाम पार्टियों पर रोक लगाकर बहुत सारे वाम तथा ट्रेड यूनियन नेताओं को गिरफ्तार कर उनपर अत्याचार चलाया. यद्यपि सी पी एस एल पर से निषेधाज्ञा को वापस लिया गया पर अन्य दो पार्टियों पर यह आदेश अभी भी जारी है. श्रीलंका सरकार की इस कार्यवाई से त्रिकोमाली को नौसेना अड्डा बनाने की अमरीकी प्रयासों को मदद मिली जो पूरे भारत उप-महादेश के लिए खतरे का कारण बन गया.

यह बैठक श्रीलंका की सरकार से आग्रह करता है कि प्रभावित लोगों को फिर से बसाने तथा उन्हें उपयुक्त मुआवजा देने के लिए उचित तथा कारगर कदम उठाये.

अन्तर्राष्ट्रीयता तथा अलगाववादी दृष्टिकोण की भर्त्सना करते हुए, बैठक की यह राय है कि श्रीलंका की नस्ली समस्याओं का एकमात्र उचित समाधान है तमिल अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्रीय स्वायत्त शासन, जिसे भारत सरकार के सहयोग से किया जाना चाहिए. यह बैठक, श्रीलंका के मजदूर-वर्ग तथा मेहनतकशों के दोनों सम्प्रदायों से वर्ग के रूप में एकजुट होकर श्रीलंका के शासकवर्ग की फूटपरस्त नीतियों के खिलाफ लड़ने तथा बेरोजगारी व गरीबी को मिटाने के लिए आह्वान करता है. यह सम्मेलन भारत के मजदूर-वर्ग का आह्वान करता है कि वे स्थिति को सामान्य बनाने तथा समस्याओं का समाधान के लिए उठाई जा रही जनवादी कार्यवाईयों की सहायता एवं समर्थन करें.

पाकिस्तान में जनतंत्र बहाली के आंदोलन पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक पाकिस्तान में जनतंत्र की बहाली तथा 1973 के संविधान को कायम किए जाने के लिए फौजी शासन के खिलाफ वहां के मजदूर-वर्ग तथा जनता के शानदार संघर्ष की सराहना करता है.

पाकिस्तान के लोगों की आजादी के बाद से ही एक के बाद एक फौजी शासनों के पीड़ा से गुजरना पड़ा. अमरीकी साम्राज्य-वाद के बढ़ते षडयंत्र ने जिया-उल हक के शासन को सबसे अत्याचारी बना दिया जिसने संविधान को उखाड़ फेंका, लोगों के जनवादी अधिकारों को नंगेरूप से कुचल कर रख दिया, तमाम राजनीतिक तथा ट्रेड यूनियन गतिविधियों को बंद कर दिया, लोगों पर बर्बर दमन चलाकर बहुतों को जेलों में भर दिया, कत्लेआम किया गया और इस्लामी कानून के नाम पर महिलाओं पर खुलेआम अत्याचार चलाया.

यह बैठक, जंगी शासन द्वारा चलाये जा रहे इस बर्बर अत्याचारों तथा जनवादी आन्दोलनों को कुचलने की शर्मनाक साजिशों की भर्त्सना करती है तथा मजदूर-वर्ग, मध्यम-वर्गीय कर्मचारी, महिलाएं, वकीलों, छात्रों आदि जनता के इन व्यापक हिस्से द्वारा देश के विभिन्न भागों में चलाए जा रहे बहादुराना संघर्षों के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करता है. पाकिस्तान को अमरीकी साम्राज्यवाद का अड्डा बनाने की जंगी शासक के षड्यन्त्र की भर्त्सना करने तथा इन नीतियों को पलटने की मांग किए जाने के लिए, यह बैठक, पाकिस्तान के जनवादी लोगों की सराहना करती है.

युद्ध के खतरे व शांति के लिए संघर्ष पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू का यह कार्यकारिणी बैठक निरस्त्रीकरण पर जेनिवा वार्त्ताओं को व्यर्थ करने तथा ग्रेट ब्रिटेन एवं पश्चिम जर्मनी में पर्शिग-II तथा क्रूईस मिसाईलें तैनात करने की रीगन प्रशासन के साजिशों के कारण पैदा हुए नाभिकीय युद्ध के बढ़ते खतरे पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है.

जेनिवा वार्त्ताओं के दौरान, नाटो तथा वार्सा संधि देशों के बीच मिसाईलों के संतुलन को बनाये रखने के लिए सोवियत संघ द्वारा पेश की गई सारे तर्कसंगत प्रस्तावों को ठुकराते हुए अमरीकी साम्रज्यवाद ने यह खुलासा कर दिया कि उनकी युद्धोन्मादना सिर्फ सोवियत संघ पर नाभिकीय बढ़त हासिल करने पर ही सीमित नहीं बल्कि पूरे समाजवादी व्यवस्था को ध्वंस करने और दुनिया पर हावी होने के लिए भी है. अमरीका के इस खतरनाक एक तरफा कार्रवाई के कारण सोवियत संघ के पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं रह गया कि वह जेनिवा वार्त्ताओं से बाहर आ जाय तथा विश्व शांति को सुरक्षित करने और मानव जाति को नाभिकीय विनाश से बचाने के लिए उचित कार्रवाई करें.

दुनिया पर हावी होने की अपनी साजिश में, दुनिया के विभिन्न कोने में हो रहे मुक्ति आन्दोलनों में खुल्लम-खुल्ला हस्तक्षेप करते हुए तथा वहां के फासिस्टों एवं तानाशाह शासक-वर्ग को मदद देकर, अमरीकी साम्राज्यवादियों ने तनाव को बढ़ा रही है. लोगों को भ्रमित करने के लिए जानबूझकर दक्षिण कोरियाई जासूसी विमान घटना कराई गई. ग्रेनाडा के क्रांतिकारी सरकार को उखाड़ फेंकना, केरिबियाई क्षेत्र में एक बर्बरतापूर्ण उकसावा था जिसके आड़ में निकारागुआ पर हमला करने तथा क्यूबा से टकराव की साजिश रची जा रही है. लेबनान में, इज्राइली आग्रासियों की मदद करने के लिए खुल्लम-खुल्ला दखलअन्दाजी दे रहे हैं. पाकिस्तान के फौजी शासक को नवीनतम हारपून मिसाईलों से इसने और भी सुसज्जित किया. और अब, योरोप के लोगों की आवाज की उपेक्षा करते हुए, खासकर पश्चिमी जर्मनी एवं ब्रिटेन में जहां इसके खिलाफ विशाल प्रदर्शनें हुई तथा संसदों में जबर्दस्त विरोध किया गया, वहां, रीगन प्रशासन और इनके नाटो सहयोगियों ने नये मिसाईलें तैनात करके जेनिवा वार्त्ताओं को एक मजाक बनाकर रख दिया.

यह कार्यकारिणी बैठक भारत सरकार से यह मांग करती है कि वह 'दो महाशक्तियों' वाली बातों के बजाय नई मिसाईलें तैनात करने की अमरीकी-नाटो मुहिम की भर्त्सना करे और उनसे यह मांग करें कि नई मिसाईलें तैनात करने से बाज आयें ताकि जेनिवा वार्त्ताओं को फिर शुरू किए जा सकें और समूची दुनिया को नाभिकीय विनाश से बचाया जा सके.

इस संकटपूर्ण परिस्थिति में, यह कार्यकारिणी, राज्य कमेटियों तथा सम्बन्ध यूनियनों को आह्वान करती है कि अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर शांति के लिए संघर्षों का एक लगातार कार्यक्रम तैयार करें तथा जनता को लामबंद कर भारत सरकार को उचित कदम उठाने के लिए मजबूर करें.

महंगाई पर

जमशेदपुर में नवम्बर 30 से 2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक अनियंत्रित रूप से सामानों की कीमतों में वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करती है. स्थिति की गम्भीरता का अन्दाजा इस बात से पता चलता है कि सितम्बर 1983 में मूल्य सूचकांक 554 प्वांइट (आधार 1960=100) पर पहुंच गई है और नौ महीनों में 59 प्वाइंटों की यह वृद्धि 1975 से इस अवधि तक के सालाना बढ़ोत्तरी में सर्वाधिक, है. इससे पहले की अधिकतम वृद्धि 49 प्वाइंटों की, 1981 में हुई थी.

इस तरह, 1980 से इन तीन साल और नौ महीनों के इन्दिरा राज में कीमतों में 50 फीसद की वृद्धि हुई. खाद्य वस्तुओं की कीमतें, जनवरी से जुलाई 1983 के दौरान 50.5 फीसद बढ़ी है. यह बजट का मूल्य-वृद्धि विरोधी होने की वित्तमंत्री के दावे का खोखलापन को सामने लाता है. तेज रफ्तार से बढ़ती महंगाई के कारण केन्द्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते की किस्त पिछले अगस्त से हर महीने बकाया हो रही है जो पहले दो महीनों पर हुआ करती थी. उन्हींके अनुसार थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई के वार्षिक दर 10 सितम्बर 1983 को 9.4 फीसद हो गई. दरअसल, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिससे आम लोगों को मतलब है) के अनुसार इसी तारीख पर, महंगाई 13.9 फीसद थी. किसानों तथा खेत मजदूरों के व्यापक हिस्से को इसी तरह लूटा जा रहा है. जन वितरण प्रणाली धराशायी हो जाने के कारण स्थिति और भी गम्भीर हो गई है.

इन परिस्थितियों में, कार्यकारिणी की यह समझदारी है कि जबतक किसानों, खेत मजदूरों सहित मेहनतकश मजदूरों के सभी हिस्सों को लामबंद कर सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक शक्तिशाली एकजुट संघर्ष नहीं चलाते तो उन्हें जीवनयापन के न्यूनतम स्तर को भी कायम रखना मुश्किल होगा.

यह बैठक इस बात पर संतोष प्रकट करता है कि दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन भी इस सवाल पर विचार किया. इस सवाल पर आठ विपक्षी पार्टियों द्वारा संयुक्त आंदोलन किए जाने के फैसले का भी यह बैठक समर्थन करता है. यह बैठक, राज्य कमेटियों तथा सीटू यूनियनों का आह्वान करता है कि कीमतों को नियंत्रित करने तथा जन वितरण प्रणाली को कारगर व शक्तिशाली बनाने के लिए एवं खाद्यान्न के थोक व्यापार का अधिग्रहण की मांगों को लेकर, अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर आंदोलन का कार्यक्रम तैयार करें.

तालाबंदियों पर

जमशेदपुर में नवम्बर 30 से 2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू का यह कार्यकारिणी बैठक तालाबंदियों की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करता है. मजदूरों को आत्म समर्पन करने में मजबूर करने के लिए मालिकान इसका

इस्तेमाल कर रहे हैं. 1982 जिसे प्रधानमंत्री द्वारा उत्पादकता वर्ष घोषित किया गया था मजदूरों के लिए तालाबंदियों के वर्ष बन गई. सरकार की अपनी ही दस्तावेजों के अनुसार 1982 वर्ष से हड़तालों के अनुपात ज्यादा श्रम दिवस तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए. जनवरी से मई 1983 के इस अवधि में तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवस 52 फीसदी हो गई है. मालिकों द्वारा सबसे जघन्य हमला पश्चिम बंगाल में चलाया गया जहां जनवरी 1982 से मई 1983 के अवधि में तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवस 85 फीसदी तक पहुंच गई. सिर्फ जूट उद्योग में ही करीब 15 से 20 मिलों में एक के बाद एक में तालाबंदी घोषित होने के कारण करीब 70,000 मजदूर प्रभावित हुए. उत्पादन मूल्य घटाने तथा यांत्रिकरण, कम्प्यूटराइजेशन एवं ऑटोमेशन के जरिए और अधिक मुनाफे की इस खोज के सामने मजदूरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मालिकान द्वारा अपनाए गए इस नए हमले के खिलाफ पिछले दो सालों से मजदूर लम्बी लड़ाइयां लड़ते रहे हैं. जबकि सरकार इन तालाबंदियों के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करती है, हड़तालों के खिलाफ काले कानूनें लागू कर रहे हैं और अपने पिछलग्गुओं के सहारे मजदूरों पर भयानक दमन चलाने के लिए मालिकान को खुले दिल से सहायता देती है. इन समाज विरोधी कार्यों के खिलाफ तमाम मजदूर वर्ग को संघर्ष के नए तरीके अपनाते हुए दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा तथा मजदूरों के प्रति समर्थन के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए जनसमर्थ जुटाना होगा. बैठक राज्य कमेटियों एवं सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करता है कि संघर्ष को विकसित करने के लिए संगठन को चुस्त-दुरुस्त बनाएं.

क्लोजर, औद्योगिक रूग्णता तथा डिनोटिफिकेशन पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू का यह कार्यकारिणी बैठक क्लोजर, व औद्योगिक रूग्णता के बढ़ते घटनाओं पर गम्भीर चिंता व्यक्त करता है. पिछले सितंबर में श्रम मंत्री सम्मेलन के लिए सरकार द्वारा पेश की गई कागजातों के अनुसार 1981 वर्ष में औद्योगिक विवादों के कारण हुए मिलबंदियों की संख्या थी 311 जबकि अन्य कारणों के लिए 350 मिले बंद हुई, 1982 में, अन्य कारणों के लिए हुई क्लोजरों की संख्या हो गई 442, जबकि औद्योगिक विवाद के कारण यह संख्या घटकर हो गई 188. यद्यपि सरकार मिलबंदियों की तथा उससे प्रभावित मजदूरों की कुल संख्या के बारे में पूरी तस्वीर नहीं पेश करती फिर भी ऊपर के आंकड़ों से इस बात का खुलासा होता है कि मालिकान के हमले बढ़ा रहे हैं. इसके साथ औद्योगिक रूग्णता की बढ़ती घटनाएं भी हैं. उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है दिसम्बर 1979 से जून 1982 तक बीमार उद्योगों की संख्या में 27 फीसदी की वृद्धि हुई. बड़े इकाइयों में (378 से 422) तथा छोटे इकाइयों में (20,975 से 25,342)—दोनों ही में रूग्णता बढ़ी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 1979 को खत्म होने वाली तीन महीनों में 52 फीसदी औद्योगिक रूग्णता का कारण कुप्रबंध तथा कोष को अन्य उद्योगों में लगाना, बताया गया है. मंदी, बिजली में कटौती, कच्चे माल की कमी आदि को अन्य कारणों में बताया गया. तथा कथित श्रमिक अशांति के कारण सिर्फ 2 फीसदी मिलबंदी हुई. इन आंकड़ों से यह साफ जाहिर होता है कि यह संकट विकास के पूंजीवादी रास्ते पर चलने के कारण हुआ. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शर्तों के तहत आयात नीति को और उदार बनाने के कारण उद्योगों में रूग्णता बढ़ रही है और यह बन्द की जा रही है. इन परिस्थितियों में, आई आर सी आई के गठन तथा उद्योगों को स्वस्थ बनाकर अंत तक राष्ट्रीयकरण करने के, उद्देश्य को ही नाकाम करते हुए सरकार इसे पुराने मालिकान को वापस देने की एक खतरनाक नीति अपना रही है जिसका मतलब होगा इन कम्पनियों का दिवालियापन जिससे हजारों मजदूर फिर से बेरोजगार बना दिए जायेंगे.

सरकार की वर्ग-पक्षपात तब सामने आती है जब हम देखते हैं कि कोष को अधिक मुनाफे वाले उद्योगों में लगाने के कारण बीमार बनी कई एम आर टी पी घराने के खिलाफ कार्यवाई करने से वह इंकार करती है. उन इकाईयों को भी सरकार राष्ट्रीयकरण करने से इन्कार करती है जिसमें सार्वजनिक वित्त संस्थाओं का ज्यादा ईक्वीटि शेयर है. इससे साफ जाहिर है कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने से सरकार का इंकार करने का कारण है आई एम एफ का दबाव जो निजी क्षेत्र को और शक्तिशाली बनाने का निर्देश देती है. मजदूरों सरकार को धोखा देने के लिए यह प्रचार कर रही है कि बीमार इकाईयों को सहकारिताओं के जरिए चलाने के लिए मजदूरों को सौंप दी जाय जबकि यह अच्छी तरह जानती है कि यह चलाया नहीं जा सकता हैं क्योंकि कोष के अलावे कच्चा माल, मार्केट आदि के सवाल भी इसके साथ जुड़ी हुई है.

यह बैठक, इन सवालों तथा तालाबंदियों के सवाल पर संयुक्त आन्दोलन चलाने की आठ विपक्षी पार्टियों के फैसले को सम्पूर्णरूप से समर्थन करता है तथा राज्य कमेटियों एवं सम्बद्ध यूनियनों को आह्वान करती है कि राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा बुलाए गए विशेष कन्वेन्शन को सफल बनाएं. उद्योगों में बंदी तथा सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीयकरण करने से इन्कार करना समाज विरोधी कार्य है. इसलिए बन्द तथा बीमार इकाईयों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग को लेकर जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए तमाम मजदूर-वर्ग को उठ खड़ा होना पड़ेगा.

फूट परस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष पर

जमशेदपुर में 20 नवम्बर से 2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक फूटपरस्त ताकतों की बढ़ती गतिविधियों पर, जो देश की व मजदूर-वर्ग की एकता को खण्डित करना चाहती है, गहरी चिंता व्यक्त करती है. हैदराबाद की साम्प्रदायिक दंगा, मजदूर-वर्ग एकता को खतरे में डालने की एक और मिसाल है. आर एस एस, जमायते इस्लामी आदि साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा देश में आर्थिक व जनवादी प्रगति के लिए किए जा रहे संघर्षों से मेहनतकशों के सभी हिस्सों को अलग करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक व जाति-भेदों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे देश की अखण्डता और एकता को और भी खण्डित करने में साम्राज्यवादी साजिशों के लिए मददगार साबित हो रही है.

पंजाब और असम, देश में पृथकतावादी तथा फूटपरस्त ताकतों के बढ़ते गतिविधियों की ओर निर्देश करता है, जिन्हें विदेशों से सहायता की जा रही है. शासक कांग्रेस(आई) पार्टी न केवल देश की एकता की रक्षा करने में असमर्थ है बल्कि मौकापरस्ती के साथ चुनावी लाभों के लिए पृथकतावादी व साम्प्रदायिक ताकतों के साथ गठबन्धन करती है. सरकार सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाईयों पर ही भरोसा करती है. इस अलगाव-वादी भावनाओं के खिलाफ, न तो कोई कदम उठाती है और न ही लोगों को जागरुक करती है.

कांग्रेस(आई) की इस दृष्टिकोण का फायदा उठाकर विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा तथाकथित 'एकात्मकता यज्ञ' के जरिए, देश भर में हिन्दू धर्मान्धता भड़काने की कोशिश की जा रही है जिस पर चिंता व्यक्त की जा रही है.

यह बैठक, पंजाब तथा हैदराबाद में हुए हत्याओं की भर्त्सना करती है साथ ही साथ इन फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ शख्त कार्रवाई करने से इंकार करने के लिए केन्द्र में कांग्रेस(आई) सरकार की निंदा करती है.

इन जघन्य हमले का मुकाबला करते हुए देश की एकता तथा अखण्डता की रक्षा करने के लिए, राज्य कमेटियों खासकर पंजाब, असम तथा आंध्र प्रदेश के कमेटियों तथा तमाम वाम व जनवादी शक्तियों की यह बैठक प्रशंसा करती है.

यह बैठक, फूटपरस्त शक्तियों के खिलाफ संयुक्त आन्दोलन का निर्माण करने की आठ विपक्षी पार्टियों के फैसले को पूरी तरह समर्थन करता है तथा राज्य कमेटियों एवं सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि संगठन को चौतरफा रूप से चुस्त-दुरुस्त कर इन ताकतों के खिलाफ एक जबर्दस्त एकजुट संघर्ष का निर्माण करने के लिए सभी तबके के मजदूर-वर्ग तथा अन्य ट्रेड यूनियनों को लामबंद करें.

किसानों व खेत मजदूरों के संघर्ष पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक देशभर के तीस लाख खेत मजदूरों का गर्मजोशी से अभिनन्दन करती है जिन्होंने जमींदारों और देहात के नीहित स्वार्थों के बर्बर शोषण से खेत मजदूरों को मुक्त करने के लिए एक व्यापक केन्द्रीय कानून बनाने की मांग पर 15 जुलाई को सफल हड़ताल किया. यह बैठक अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन तथा भारतीय खेत मजदूर यूनियन को संयुक्त रूप से हड़ताल का आह्वान करने के लिए भी अभिनन्दन करती है. 25 जुलाई को पश्चिम बंगाल में संयुक्त-रूप से एक जबर्दस्त हड़ताल का आयोजन करने के लिए प. बंगाल किसान सभा तथा अन्य खेत मजदूर संगठनों की भी प्रशंसा करती है. हड़ताली मजदूरों के साथ एकजुटता का इजहार करने के लिए सीटू राज्य कमेटियों की यह बैठक प्रशंसा करती है. यह बैठक, बिहार, प. बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं अन्य राज्यों में विशाल किसान रैलियों का आयोजन किए जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है.

एक व्यापक कानून बनाने की 1980 में भारत सरकार द्वारा दिए गए वादे से यह कहकर मुकर जाना कि इस संदर्भ में राज्यों के बीच मतभेद है—इसका यह बैठक विरोध करती है. वास्तव में जमींदारों तथा देहात के नीहित स्वार्थों के दबाव के आगे सरकार घुटने टेक रही है जिसके कारण उनके संघर्षों को कुचलने के लिए खेत मजदूरों पर जमींदारों के अत्याचार और भी बढ़ गए हैं.

इसलिए यह बैठक राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे किसान व खेत मजदूरों के संगठनों के साथ गठबन्धन बनाने के लिए पहलकदमी करें तथा उनके हितों की रक्षा के लिए भी संघर्ष करें.

सार्वजनिक क्षेत्र के त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता कमेटी पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर '1983 को संपन्न सीटू का यह कार्यकारिणी बैठक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्त में बढ़ोत्तरी के सवाल पर सरकार द्वारा बिलम्बकारी नीति अपनाई जाने की अड़ियल रवैये पर अपनी गम्भीर चिंता व्यक्त करता है.

सरकार ने पहले, त्रिपक्षीय समिति के गठन में ही बाधा डालने की कोशिश की और बाद में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के साथ 18 जनवरी, 1983 को हुए समझौते में गतिरोध पैदा करने के उद्देश्य से संदर्भ शर्तों में बेतुकी बातों को लाने लगी. और उस समय से ही मजदूरों को उनके जायज मांगों से बंचित करने के ध्येय से बढ़ोत्तरी के सवाल पर ढुल-मुल रूख अपनाा रही है.

यह बैठक सरकार को सचेत करती है कि वित्त मंत्री ने केन्द्रिय ट्रेड यूनियनों के समक्ष यह स्वीकार किया था कि महंगाई के वर्त्तमान 1.30 रू प्रति प्वाइंट के दर जीवनयापन के न्यूनतम स्तर पर भी खर्च को भरपाई नहीं करती और बढ़ोत्तरी के दर को तय करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठन किए जाने की बात सरकार मान लेने के बाद ही सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के हड़ताल को स्थगित किया गया था. जबकि ट्रेड यूनियनों ने अपनी सहयोगितापूर्ण रूख का प्रदर्शन करते हुए 2.50 रू प्रति प्वाइंट की अपनी पहली मांग से 2.00 रू प्रति प्वाइंट मानने में राजी हुए, भारत सरकार अपनी 1.50 रू प्रति प्वाइंट जो मूल्यों में वृद्धि को पूरी तरह खत्म नहीं करती, से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं. इसके पूर्वापेक्षी प्रभाव के सवाल पर सरकार द्वारा अपनाई जा रही-रूख से बातार्ओं में कोई प्रगति नहीं हुई. जबकि ट्रेड यूनियनों ने इन सिफारिशों को 1 जनवरी '1983 से लागू करने की सही मांग की है सरकार 1 जून '1983 से इसे देना चाहती है.

सरकार की इस अड़ियल रवैये से यह स्पष्ट होता है कि संघर्ष किए बिना इस सवाल पर फैसला नहीं हो सकता. यह बैठक इस बात पर प्रसन्नता प्रकट करता है कि इस सवाल पर इंटक भी अन्य केन्द्रिय ट्रेड यूनियनों जैसा रूख अपना रहा है. इसलिए यह बैठक अपने राज्य कमेटियों से यह आह्वान करता है कि अन्य केन्द्रिय ट्रेड यूनियनों के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के बीच अभियान चलाकर उन्हें एकजुट संघर्ष के लिए लामबंद करे ताकि मूल्यों में वृद्धि को पूरी तरह खत्म करने की उनकी मांग को मान लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके.

जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर '1983 को सम्पन्न सीटू का यह कार्यकारिणी बैठक सभी पार्टियां तथा सारे ट्रेड यूनियनों के सर्वसम्मत मांग के बावजूद भारत सरकार द्वारा जूट उद्योग की राष्ट्रीयकरण करने से इंकार किए जाने की कड़ी भर्त्सना करता है.

जूट मजदूरों के पचास दिनों के हड़ताल के कारण 1979 में हुए त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए पांच इजारेदार जूट घराने द्वारा 2.5 लाख जूट मजदूरों एवं लाखो जूट उत्पादकों को तबाही के कगार पर ढकेलते हुए बेतहास मुनाफा लूटी जा रही है. ये जूट सेठों ने ग्रेडों तथा वेतन मानों और काम के सिलसिले में कमेटी के सिफारिशों तथा प. बंगाल श्रम-मंत्री के सिफारिशों को लागू करने से इंकार करते रहे हैं. न्यायालय की राय उनके खिलाफ होने के बावजूद ये समझौते का उल्लंघन करते रहे. पिछले तीन सालों से 15-20 मिलों में तालाबंदियों से सत्तर हजार मजदूर प्रभावित रहें. लगातार प्रयासों के बावजूद भी केन्द्र सरकार, जूट सेठों को समझौते को मानने के लिए मजबूर करने पर, कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं. इसके विपरीत, कच्चे जूट की खरीद के लिए इन्हें दिए गए करोड़ों रूपये को अन्य मुनाफेवाले उद्योगों में लगाने की छूट दे रही है. इसी तरह का शोषण कानपुर में भी जारी है जहां जे के जूट मिल्स् के प्रबंधकों ने सरकार की मदद से मजदूरों पर बर्बर दमन चला रखा है.

राष्ट्रीयकरण की मांग को अब पश्चिम बंगाल के सभी पार्टियों तथा सभी तबके के लोगों द्वारा समर्थन किया जा रहा है. राज्य विधान सभा ने सर्वसम्मति प्रस्ताव के जरिए इसका समर्थन किया. कांग्रेस (आई) सहित विधान सभा के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 29 जून को प्रधानमंत्री से मिलकर इस मांग को मान लेने के लिए कहा.

यह बैठक, जूट सेठों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मजदूरों के इस फौरी मांग को ठुकरा देने की कड़ी भर्त्सना करता है. जूट मजदूरों तथा यूनियनों के 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल के सर्वसम्मति फैसले का यह कार्यकारिणी बैठक प्रशंसा करता है तथा राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों तथा अन्य सभी ट्रेड यूनियनों का आह्वान करता है कि कच्चा जूट तथा इसके निर्यात सहित समूची जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण कि मांग पर हो रहे इस संघर्ष के साथ सम्पूर्ण एकजुटता का इजहार करें.

कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से बम्बई के 13 बन्द कपड़ा मिलों को अधिग्रहण करने की भारत सरकार के फैसले का स्वागत करती हैं. इससे 36,000 मजदूरों को लाभ होगा जिन्हें मिल मालिकों के अड़ियल रवैये के कारण बेरोजगार रहना पड़ा था. बहरहाल, यह बैठक सिर्फ बम्बई के इन 13 मिलों के अधिग्रहण को विभिन्न राज्यों में बहुसंख्यक मिलों में क्लोजर से प्रभावित हजारों मजदूरों की सहायता में एक निहायत ही छोटा कदम समझती है.

जबकि बम्बई में ही, मालिकान तथा सरकार द्वारा मजदूरों की मांगे मानने से इन्कार करने का अड़ियल रुख के कारण 40 से भी अधिक मिलों में बर्बादी की स्थिति बनी हुई है, हरियाणा, तमिलनाडु पांडिचेरी, उड़ीसा, प. बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में भी मिल मालिकों द्वारा इसी तरह का रुख अपनाई जा रही है. सरकार द्वारा अधिग्रहित कई मिलों को, जिसे नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन के तत्वाबधान में चलाई जा रही है, अभीतक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया. एन टी सी मैनेजमेंट के व्यापक भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सभी

मिलों से मिल रही है. मजदूरों के शोषण, धांधलियों आदि से बेतहाशा मुनाफा लूटने का क्रम जारी है. 26 एन टी सी इकाईयों को, जिसमें 12 प. बंगाल में हैं, बन्द कर दिए जाने के केन्द्र सरकार के प्रयासों पर यह बैठक गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है.

इसलिए, सीटू, केन्द्र सरकार को यह चेतावनी देती है कि अगर इस प्रस्ताव को कारगर रूप दिया गया तो कपड़ा उद्योग में एक भयानक गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी और इसलिए यह मांग करता है कि प्रस्ताव को तत्काल वापस लिया जाय जिससे हजारों मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा पर आनेवाले खतरे को टाला जा सके.

यह बैठक समूचे कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने की मांग करती है तथा मजदूर-वर्ग को इस मांग के समर्थन में आवाज बुलन्द करने का आह्वान करती है.

कामगार महिलाओं पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक महिलाओं की तेजी से बिगड़ती दशा के प्रति केन्द्र सरकार की उदासीन रुख की निन्दा करती है. रोजगार क्षेत्र में इनकी स्थिति और भी बिगड़ गई है. 1980 के अन्त तक पंजीकृत महिलाओं की संख्या 23.45 लाख थी जो पिछले साल की तुलना में 4 लाख से भी अधिक थी और दिसम्बर 1982 के अन्त तक यह संख्या 31.38 लाख हो गई है. लगभग सभी उद्योगों. कार्यालयों व प्रतिष्ठानों में समान पारिश्रमिक कानून को लागू किए जाने के बावजूद भी इनके वेतन में भेदभाव किया जाता है.

यह कार्यकारिणी, महिलाओं के लिए कल्याण मूलक कदम उठाने, उनके लिए रोजगार के क्षेत्र खोलने, उनपर हो रहे अत्याचारों से उन्हें बचाने में सरकार की नाकामयाबी की निंदा करती है. यह बैठक, महिलाओं तथा विभिन्न महिला संगठनों द्वारा उनपर हो रहे अत्याचारों या किए जा रहे भेद-भावों के खिलाफ चलाये जा रहे संघर्षों तथा मांगों के समर्थन में पार्लियामेंट मार्च के कार्यक्रम की प्रशंसा करती है. यह बैठक, इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करती है कि दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन के फैसले के अनुसार, राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा महिलाओं की विशेष सम्मेलन की तैयारियां की जा रही हैं. इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अधिकाधिक महिलाओं को लामबंद करने के लिए यह बैठक राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है.

अपने दिशा निर्देशन में कामगार महिलाओं के कोआर्डिनेशन कमेटियां बनाने और उन्हें देश के मजदूर-वर्ग आन्दोलन के मुख्यधारा में शामिल करने की सीटू के पांचवें सम्मेलन के इस फैसले के प्रति यह बैठक, राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों का ध्यान आकर्षण करती है.

यह बैठक, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश के राज्य कमेटियों द्वारा इस दिशा में कदम उठाने के लिए बधाई देती है तथा अन्य राज्य कमेटियों से इस प्रक्रिया को आरम्भ करने का आह्वान करती है.

केन्द्र सरकार कर्मचारियों के संघर्ष पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक राज्य सरकार कर्मचारियों का गर्मजोशि से अभिनन्दन करती है जिन्होंने केन्द्र सरकार को बोनस की बुनियादी मांग को मान लेने में मजबूर किया. सरकार ने इन्हें 15 दिन के वेतन के समान बोनस की घोषणा की है. सरकार ने केन्द्र सरकार कर्मचारियों तथा विभागीय कर्मचारियों के बीच फूट डालने की पूरी कोशिश की इसके बावजूद यह सफलता कर्मचारियों के सभी तबकों को एकजुट करने के अथक प्रयासों के कारण ही सम्भव हुई.

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के समान वेतन की उनकी मांग को सरकार अभी तक नहीं मानी है. इसके विपरीत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का वेतन जाम करने की कोशिश की जिसे मजदूरों के एकजुट दृढ़ संघर्ष ने नाकाम किया। और सरकार को 1979 और 1983 में इनके वेतन में वृद्धि करने में मजबूर किया. चौथी वेतन आयोग के गठन के समय सरकार द्वारा दिये गये एक तुच्छ अन्तरिम राहत के प्रस्ताव से ही सरकार की नीयत का पता चलता है. कर्मचारियों के 150 रु. अन्तरिम राहत की मांग जायज थी पर इस सवाल पर समझौता कर लेने के कारण वेतन में समानता के लिए संघर्ष को काफी नुकसान पहुंचा, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट ने भी समान काम के लिए समान वेतन की नीति के पक्ष में राय दी थी.

यह बैधक, केन्द्र सरकार कर्मचारियों द्वारा अपने मांगों के लिए एकजुट संघर्ष की बढ़ते समझदारी पर सन्तोष प्रकट करता है और यह आशा करती है कि केन्द्र सरकार कर्मचारियों के सभी हिस्सों को, सभी संगठनों को, लामबंद कर, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ वेतन में समानता की अपनी मांग के समर्थन में एक जुझारू संघर्ष करेंगे.

केन्द्र सरकार कर्मचारियों के इस जायज संघर्ष में सीटू अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन देती है.

रेलवे मजदूरों के संघष पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक भारतीय रेलवे की स्थिति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है. भारत में पूंजीवादी योजनाओं में बिफलता के कारण देश की विकास योजनाओं के महत्वपूर्ण ढांचा भारतीय रेल प्रणाली में भारी बिगड़ाव आया है. कुछ

सालों के लिए तो माल ढ़ोने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी और अब यात्रि यातायात के मामले में भी असफल हो रही है. रेल प्रणाली के अस्वस्थ्य होने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही है जिसके फलस्वरूप हर साल 300 लोगों की जानें जा रही हैं. भारत सरकार द्वारा अंधाधुंध कम्प्यूटर बैठाये जाने के कारण बहुत जल्द ही रेलवे में 9 लाख लोग बेरोजगार हो जायेंगे. मजदूरों को काम से निकालना शुरू हो गया है. कोयला मजदूरों की बड़े पैमाने पर छंटनी की गई, लाइनों का काम ठेका मजदूरों को दिया जा रहा है. लोको रनिंग स्टाफ ऐसोसिएशन के साथ अधिकाधिक दस घण्टे लगातार काम के समझौते को ताक पर रखते हुए, काम के बढ़ते बोझ के खिलाफ हो रहे सभी संघर्षों को बेरहमी से दमन किया जा रहा है.

इसके अलावा, रेल मजदूरों ने जिन मांगों को लेकर 1974 की ऐतिहासिक हड़ताल की उसे भी अभी तक नहीं माना गया रेल मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों के बर्बर दमन से स्थिति में और भी बिगड़ाव आया है और इसके मुकाबला के लिए रेल-कर्मियों के तमाम ट्रेड यूनियन आन्दोलनों का तत्काल एकजुट होना बहुत जरूरी है. यह दुर्भाग्यजनक है कि फरवरी से, व्यापक एकता को कायम करने के इनके प्रयासों को धक्का पहुंचा था, पर 19 अगस्त के बोट क्लब के समक्ष प्रदर्शन तथा 28 अगस्त को एक कन्वेन्शन के माध्यम रेल मजदूरों के राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन के जरिये उन्होंने इसके खिलाफ अपना रोष प्रकट किया. पिछले दो सालों के घटना विकास से यह देखा जा रहा है कि व्यापक एकता और जुझारू संघर्ष के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों ने अपनी मांगें हासिल करने तथा ट्रेड यूनियनों पर हो रहे हमले को रोकने में कामयाब हुए. जबतक रेल मजदूर एकजुट नहीं होते तबतक सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के समान वेतन की अपनी मांग को हासिल नहीं कर पायेंगे.

यह बैठक रेल मजदूरों को सचेत करती है कि उनके अंदर फूट डालने तथा उनके खिलाफ आम-जनता को भड़काने की सरकार अपनी प्रयास जारी रखेगी. उन्हें यह भी नोट करना चाहिए कि पिछले तीन सालों में उनके वेतन में वृद्धि न होने के बावजूद यात्री किराया तथा माल भाड़ा दुगनी हो गई जिसके कारण जनता में रोष फैल रही है और इस सवाल को एल आर एस ए एवं अन्य कई संगठनों द्वारा उठाया जा रहा है.

यह बैठक, रेल मजदूरों से एक शक्तिशाली एकजुट संघर्ष का निर्माण करने का अपील करता है तथा उनके जायज मांगों के लिए संघर्षों को पूरा समर्थन देता है.

कोयला खदान मजदूरों के संघर्ष पर

जमशेदपुर में 30 नवंबर—2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू का यह कार्यकारिणी बैठक सात लाख कोयला खदान मजदूरों को उनके शानदार विजय के लिए गर्म जोशी से अभिनंदन करता है जिन्होंने केन्द्र सरकार की वेतन जाम करने की नीति को शिकस्त देते हुए अपनी मांगों को हासिल करने में सफल प्राप्त की

यह सफलता, सीटू, एटक, इंटक, एच. एम. एस. तथा बी. एम. एस. द्वारा संयुक्त रूप से 12 नवम्बर को हड़ताल और उसके पश्चात् अनिश्चितकालीन हड़ताल के आह्वान के कारण ही सम्भव हुआ. 11 नवम्बर को हस्ताक्षर हुए इस तीसरे राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता भारत सरकार तथा बी.पी.ई. के प्रति एक करारा तमाचा है जिन्होंने वार्त्ताओं के दौरान हस्तक्षेप करने की कोशिश की. इस समझौते से वेतनों में 23 फीसदी की वृद्धि हुई जो सार्वजनिक क्षेत्र के वर्त्तमान वेतन वार्त्ताओं के दौर का सबसे अधिक बढ़ोत्तरी है.

8 नवम्बर 1982 तथा 17 से 19 जनवरी 1983 के कोयला मजदूरों के देश व्यापी हड़तालों के कारण ही प्रबंधकों को झुकना पड़ा. 5 अक्तूबर के कोयला मजदूरों का सफल विरोध दिवस ने इनके एकजुटता और दृढ़ संकल्पता का एक बेमिशाल इजहार था जिसे सरकार नजर अंदाज नहीं कर सकी. इस एकजुटता को बनाए रखते हुए इसे और शक्तिशाली बनाना होगा. मजदूरों के इस कामयाबी को छिनने की कोशिश में इनके खिलाफ नई साजिशें रची जा रही है. रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व चेयर मैन एम एस गुजराल, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डाइरेक्टर के हैसियत में कार्य भार संभालने के साथ ही अत्याचार बढ़ रही है. एक दिन काम बंद करने के बदले आठ दिनों का वेतन में कटौती, सप्ताह में सातों दिन काम, यूनियन के सक्रिय सदस्यों का तबादला, बहुतों को झूठे आरोपों में चार्ज शीट तथा निलंबन आदेश आदि कार्रवाईयां जारी है.

बदनाम सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) का औद्योगिक विवादों को निपटारे के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है. समाज विरोधी एवं सी आई एस एफ के गठबंधन के कारण गैर कानूनी खनन कार्य भी शुरू हो गई है. रानीगंज कोयला क्षेत्र में सी आई एस एफ अधिकारियों ने सीटू झंडे को जलाया जिसके खिलाफ प्रबंधकों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

कोयला खदानों में उत्पादन के आंकड़े 2.5 फीसदी बढ़ाकर दिखने की सी आई. एल. चेयरमैन के इस निर्देश के कारण कोयला खदानों में धांधलियां बढ़ रही है. इसके खिलाफ ओफिर्सस एसोयियेशन के शिकायतों के बावजूद भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं की.

एन सी डब्लू ए-III को लागू न किए जाने के सवाल पर मजदूरों को गम्भीरता से विचार करना होगा. लगातार आंदोलन के बिना पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान एवं

अन्य सुविधाओं के प्रावधानों को कोयला कम्पनियां सही तरीके से लागू नहीं करेंगी.

कोयला क्षेत्र के मजदूर यांत्रिकरण के कारण बेरोजगार होने के डर से चिंतित हैं. कामगार महिलाओं को पहले की ही तरह आक्रमण का निशाना बनाया जाता है और आश्वासन के बावजूद सरकार अभी तक कुछ नहीं की है.

खदान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन जारी है. खदान सुरक्षा कांउसिल के फैसले को अभी तक लागू नहीं किया गया, फलस्वरूप दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही है. हाल की हरलडीह दुर्घटना से यह जाहिर है कि चासनाला के अनुभवों के बाद भी सुरक्षा संबंधी कोई कदम नहीं लिया गया था यह बैठक इस लिए, यह मांग करता है:

सभी कोयला खदानों से सी आई एस एफ को तत्काल वापस बुलाई जाय. दूसरा एवं तीसरा राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते को सम्पूर्ण रूप से लागू की जाए.

एक दिन के हड़ताल के लिए आठ दिनों का वेतन काटना बंद की जाय तथा अब तक की गई कटौती को मजदूरों को वापस की जाय

कोयला खदानों में सप्ताह में सात दिनों का काम को रद्द करते हुए सबके लिए एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान की जाय.

कोयला खदानों में यांत्रिकरण को बंद करते हुए महिलाओं सहित सभी मजदूरों के नौकरी को सुरक्षित की जाय.

सभी सुरक्षा प्रावधानों को कार्यकारी बनाई जाय तथा सुरक्षा सम्बंधी सम्मेलन के फैसलों को लागू की जाय.

यह बैठक कोयला उद्योग के सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन एवं राष्ट्रीय फेडरेशनों से एकजुट होकर एक देशव्यापी आंदोलन चलाने का आह्वान करता है जिससे इन मांगों को हासिल की जा सके.

यह बैठक, सम्बंद्ध यूनियनों का आह्वान करता है कि अपने संगठन को शक्तिशाली बनाएँ तथा स्थानीय स्तर पर भी एकजुट आंदोलन के निर्माण में पहल कदमी दिखायें जो एक देश व्यापी एकजुट आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध होगी.

ट्रेड यूनियन (पश्चिम बंगाल) संशोधन बिल पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा सरकार को, ट्रेड यूनियन (पश्चिम बंगाल) संशोधन बिल बनाने के लिए, बधाई देती है. इस बिल के जरिये, ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है. इस सिद्धांत की मान्यता के लिए सीटू अरसे से मांग करती आ रही है. यह बिल, मजदूरों के प्रति तथा उनके पसंद की यूनियन चुनने वा बनाने की मजदूरों के जनवादी अधिकारों के प्रति वाम मोर्चेवाली सरकार तथा कांग्रेस(आई) सरकार के दृटिकोण में भिन्नता को दिखाता है.

इसके अलावा, अगर कोई मालिक इसके प्रावधानों के अनुसार किसी यूनियन को मान्यता देने से इंकार करती है तो उनके लिए उचित सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया है. इससे पक्षपात को रोका जायगा, समझौतों को स्वीकृति मिलेगी तथा औद्योगिक शांति बनी रहेगी.

इस पर ध्यान रखते हुए कि 1969 में राज्यसभा द्वारा पारित ऐसी ही एक बिल को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न होने के कारण, 13 साल के बाद वापस किया गया, यह कार्यकारिणी सभी राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों को इस बिल के समर्थन में अभियान चलाने तथा इसे मंजूरी देने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने की अपील करती है. अन्य राज्यों में भी इस तरह के बिल लाये जाने के लिए संयुक्त आन्दोलनों का निर्माण करना होगा जिससे गुप्त मतदान के जरिये यूनियनों की मान्यता की बात भारत सरकार मानने में मजबूर हों.

सीटू सक्रिय सदस्यों पर गुन्डों के हमले पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक देश के विभिन्न भागों में सीटू सक्रिय सदस्यों पर मालिकान के भाड़े के टट्टूओं तथा अन्य ट्रेड यूनियनों के विघटनकारी तत्वों द्वारा किए जा रहे हमले की तीव्र भर्त्सना करती है.

सबसे कायरतापूर्ण हमला 9 जुलाई को मोदीनगर में हुई, जसमें एच एम एस के सदस्यों ने पांच सीटू सक्रिय सदस्यों की जानें लीं. बाद में दो और की हत्या की गई. सीटू के बढ़ते प्रभाव से बौखलाकर एच एम एस के गुंडों ने इस कायरता पर उतर आए. यह बैठक पांच सीटू सदस्यों को एन एस ए में बन्द रखे जाने का विरोध करता है. यह बैठक गुंडों के खिलाफ सख्त कारवाई करने में सरकार की असफलता के प्रति भी अपना विरोध प्रकट करता है. एक और शर्मनाक हमला आर एस एस के गुंडों द्वारा उड़ीसा में की गई जहां सीटू राज्य कमेटी के सदस्य का. अनन्त राउत को खोज पाने में असमर्थ होने पर उनके पांच वर्षीय पुत्र की बर्बरता से हत्या कर दी गई. अशोक लेलैंड की तमिलनाडु होसुर इकाई में, एक और सीटू कार्यकर्त्ता की हत्या प्रबंधकों की सांठ-गाठ में प्रतिस्पर्द्धी यूनियन के गुंडों द्वारा की गई. इसी तरह के हमले बी एम एस, आर एस एस, इंटक आदि द्वारा केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान, हरियाणा, असम तथा अन्य स्थानों पर भी हो रहे हैं.

यह बैठक उन मजदूरों का गर्मजोशी से अभिनन्दन करती है जिन्होंने इन आपदाओं को झेलते हुए सीटू के झण्डे को बुलंद रखा. सरकार से इस गुंडागर्दी को बन्द करने तथा नाजायज रूप से जेलों में रखे गये सीटू सदस्यों को रिहा किये जाने की

मांग करते हुए, यह बैठक सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि सरकार तथा मालिकान की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर-वर्ग के हित के लिए, ट्रेड यूनियन आन्दोलन एकता को बरकरार रखें.

हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास फैक्ट्री पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक आसनशोल के हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास फैक्ट्री के मौजुदा हालत पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है. प. बंगाल सरकार के प्रयास से अर्से के बाद यह फैक्ट्री फिर से खोली गई थी तथा नये प्रबन्धकों के ऊपर इसे चलाने की जिम्मेदारी दी गई. पर वर्तमान प्रबन्धन भी उत्पादन बन्द कर दी है तथा पिछले अक्टूबर से मजदूरों के वेतन, आदि न देने के कारण 1,500 मजदूर अपने परिवार-वालों के साथ कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं.

मजदूरों के कठिनाईयों को दूर करने की प. बंगाल सरकार के प्रयासों को नाकामयाब करने की प्रबंधकों के इस साजिश का यह बैठक भर्त्सना करती है एवं तत्काल मजदूरों को उनके बकाया वेतन तथा बोनस देने और उत्पादन शुरू किए जाने की मांग करती है.

कालिदासपुर व कांकरतला कोयला योजना पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक कालिदासपुर व कांकरतला कोयला योजनाओं को बन्द कर देने के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्धकों की कड़ी भर्त्सना करती है. सी आई एल के इस कार्यवाई से न केवल सैकड़ों मजदूर बेरोजगार बनाए गए बल्कि समूचे कोयला उद्योग एवं आम जनता के हितों को भी हानि पहुंचाई. यह बैठक भारत सरकार तथा सी आई एल मैनेजमेंट से मांग करती है कि इन योजनाओं को तत्काल चलाई जाय.

मेटल बक्स मजदूरों के संघर्ष पर

जमशेदपुर में, 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक प. बंगाल के मेटल बक्स मजदूरों का अभिनन्दन करती है, जिन्होंने इसके पेपर व प्लास्टिक इकाई को बन्द कर दिए जाने तथा 388 मजदूरों के छंटनी के खिलाफ पिछले चार महिनों से संघर्षरत हैं. यह बैठक प्रबन्धकों के अड़ियल रवैये की कड़ी भर्त्सना करती है, जिसके कारण राज्य के वाम मोर्चा सरकार द्वारा समझौते के लिए की गई अबतक के प्रयास विफल रही. यह कार्यकारिणी मिल को तत्काल खोलने, मजदूरों के छंटनी आदेश वापस लेने तथा समझौता किये जाने की मांग करती है. राज्य के मजदूर-वर्ग और मुख्यरूप से अन्य राज्यों के मेटल बक्स मजदूरों द्वारा इस संघर्ष को दिए गये बिरादराना समर्थन की यह बैठक सराहना करती है. यह बैठक, संघर्षरत मजदूरों के प्रति सम्पूर्ण समर्थन का आश्वासन देती है तथा देश के मजदूर-वर्ग तथा जनता का आह्वान करती है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनी के अत्याचारों के खिलाफ संघर्षरत इन हड़ताली साथियों को आर्थिक सहायता सहित हर तरह के समर्थन दिये जांय.

बैंक समझौते पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2दिसंबर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक, 6 सितंबर को एक शानदार हड़ताल के लिए, बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया को बधाई देती है जिसमें अपनी सूत्री मांगों पर समझौते के लिए तथा यांत्रिकरण व कम्पूटराइजेशन के विरोध में देश भर के एक लाख कर्मचारियों में शिरकत की.

वार्ताओं में बैंक एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया को शामिल न करने की सरकार तथा इंडियन बैंक एसोसिएशन के रूख का यह बैठक विरोध करती है. यह दुखः की बात है कि बैंकों में कम्पूटर बैठाने के खिलाफ एक संयुक्त आंदोलन के बीई एफ आई के आह्वान को ठुकराकर इंडियन बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन तथा नेशनल कन्फेडरेशन आफ बैंक एम्पलाइज ने एकजुटता प्रयास के इस मौके को खो दिया. कम्पूटर बैठाने की समझौते ने बैंक कर्मचारियों को एक भारी नुकसान पहुंचाया है क्योंकि सभी उद्योगों की यह अनुभव है कि पूंजी-वादी ढांचे में कम्पूटरराइजेशन व आटोमेशन मजदूरों को बेरोजगार बनाती है. यह बैठक, हड़ताल के पहले वित्त मंत्री द्वारा राजनीतिक उद्देश्य से दिए गए झूटे बयान की निंदा करती है जिसमें यह कहा गया कि सरकार बी ई एफ आई से वार्त्तालाप करने से कभी इंकार नहीं की है और यह कि इसने अपनी सूत्री मांगें सरकार के समक्ष पेश नहीं की है पर वित्त उपमंत्री ने इससे पहले संसद में इसके मिलने को बात बता चुके थे.

समझौते को रद्द करने की बीई एफ आई द्वारा लिए गए सही निर्णय का समर्थन करते हुए यह कार्यकारिणी सारे बैंक कर्मचारियों तथा उनके संगठनों को एकजुट होकर एक संयुक्त आंदोलन छेड़ने का आह्वान करता है.

असम इंडष्ट्रीयल रिलिफ अंडरटेकिंग (विशेष प्रावधान) बिल, 1983 पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसंबर 1983 को संपन्न सीटू का यह कार्यकारिणी बैठक असम इंडस्ट्रीयल रिलीफ अंडरटेकिंग (स्पेशल प्रोविजनस्) बिल, 1983 को लाने के

लिए असम सरकार की भर्त्सना करती है, जिसमें तमाम ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा सुविधाओं को छीन लेने की साजिस रची गई है. बंद इकाइयों को खोले जाने तथा बीमार इकाइयों को चलाकर रोजगार के क्षेत्र को खोलने के नाम पर, इस बिल के जरिये सारे कल्याणमूलक श्रम कानूनों जैसे, उद्योगिक विवाद अधिनियम, स्टैंडिंग आर्डर कानून, पेमेंट अफ वेजेस एक्ट, न्यूनतम वेतन कानून, बोनस कानून, ग्रेच्युटी कानून, शप एंड एस्टाब्लिसमेंट एक्ट आदि तथा न्यायालय व ट्रीब्यूनल के फैसले तथा तमाम समझौते को पांच सालों के लिए रद्द करने की साजिश की गई. इसके अलावा इस बिल के जरिए जरूरत के मुताबिक मजदूर एवं कर्मचारियों की संख्या निर्णय करने की सम्पूर्ण अधिकार मालिकान को दी गई जिसका मतलब है कि किसी भी इकाई में कार्यरत मजदूरों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं रहेगी.

यह कार्यकारिणी, असम सरकार की इस नये हमले पर गम्भीर चिंता प्रकट करता है, जो कि असम की स्थिति को सामान्य बनाने तथा उद्योगों के विकास के दिशा में कारगर कदम उठाने के बजाय, मिलबंदी व रूग्णता के सही कारणों को खोज निकालने के बजाय तथा भ्रष्ट प्रबंधकों द्वारा कोष को अन्य उद्योगों में हटाने से रोकने के बजाय भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की प्रयास में मालिकान को और मदद दे रहे हैं. वर्तमान स्थिति का फायदा उठाकर, सरकार मजदूरों द्वारा बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त उनके अधिकारों व सुविधाओं को छिनना चाहती है और राज्य के इजारेदारों तथा पृथकतावादी शक्तियों को मदद दे रही है.

इस बिल को दृढ़तापूर्वक विरोध करने के लिए असम राज्य कमेटी को बधाई देते हुए यह कार्यकारिणी सभी राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करता है कि असम सरकार

(शेष पृष्ठ 44 पर)

(पृष्ठ 16 का शेष)

जा सके. अगर हम स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधियां बढ़ाते है तो ऐसा होना सम्भव है पर ऐसा करने में हमें बाधायें तो मिलेंगे जरूर फिर भी हमारे लक्ष्य को तथा एकजुट संघर्ष को आगे बढाना, यह हमारी जिम्मेदारियां हैं. साथ साथ यह भी समझना गलत होगा कि सारे समस्याओं का समाधान जल्द ही जाएगा क्योंकि हम पूंजीपति वर्ग का मुकाबला कर रहे हैं. इसलिए समस्याओं का समाधान संघर्ष के माध्यम ही होगा —और यह एक कठिन और लम्बी लड़ाई होगी.

हमारी मांगें धीरे धीरे सभी ट्रेड यूनियनों की मांग हो रही है जैसा जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर हम देख रहे है कि प. बंगाल में तमाम राजनीतिक पार्टियां तथा यूनियनें एक मंच पर आई है. संकट के प्रभाव से ऐसा हो रहा है— गहराते संकट की यही है प्रतिक्रिया.

क्लोजर व तालाबंदियों के सवाल पर बी टी आर ने बताया कि इन समाज विरोधी कार्यों के खिलाफ हम तमाम मजदूरवर्ग को एक बद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं. और यह काम हमें पूरी लगन के साथ करना होगा मजदूर वर्ग के अनेक हिस्से आज भी फैक्ट्री चेतना से ऊपर नहीं उठ पाये है। उन्हें राष्ट्रीय अभियान समिति के संयुक्त मंच पर लाना होगा तभी पूंजीवादी संकट के खिलाफ अपने संघर्ष को हम आगे ले जा पायेंगे। क्लोजर के खिलाफ हमारा संघर्ष, पूंजीवादी संकट के खिलाफ हमारे संघर्ष का अंग समझना होगा.

कामगार महिलाओं का विशेष कन्वेन्शन एक खास अहमियत रखता है इस लिए राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों से इसे सफल बनाने का आह्वान करते हुए बी.टी. आर ने कहा कि कामगार महिलाओं को ट्रेड यूनियन आंदोलन की मुख्य-धारा में शामिल करने में यह सहायक सिद्ध होगी.

बी टी आर ने कहा कि युद्ध के खिलाफ तथा शांति के लिए संघर्ष के सवाल पर कुछ ट्रेड यूनियन सरकार की दो महाशक्तियों वाली प्रचारों से भ्रमित जरूर हो रहे हैं पर हमें उनको सचेत करना होगा, हमारे मुख्य दुश्मन, अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ उनकी जागरूकता को बढ़ाना होगा ताकि 20 से 28 दिसंबर तक होने वाली शांति सप्ताह को हम व्यापक रूप से सफल बना सके.

फूटपरस्त वादी शक्तियों के खिलाफ एक जूट होने का आह्वान करते हुए बी टी आर ने बताया कि साम्प्रदायिक तथा पृथकतावादी तत्वों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों को मुख्य प्रतिरोध के रूप में खड़ा होकर हमारे वर्ग एकता तथा देश की अखंडता की रक्षा करनी पड़ेगी.

अपने भाषण का समापन करते हुए बी टी आर ने बताया कि मजदूरों के जनवादी तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा करना ही हमारा मूल लक्ष्य है. हमें जनवादी तरीकों से काम करना होगा—नीचे से उपर तक संगठन के सभी स्तर पर जनवादी कार्यप्रणाली को प्रसारित करना होगा. संघर्षों को सफल बनाने के लिए हमें मध्यवर्गीय सत्तावाद के बदले सर्वहारा जनतंत्रवाद को क्रियात्मक रूप देना होगा.

रैली

2 दिसम्बर को तीसरे पहर जमशेदपुर के बारी मैदान में एक विशाल रैली हुई. जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र के 25,000 मजदूरों ने इसमें शिरकत की. सुबह से ही रैली में शामिल होने के लिए विभिन्न स्थानों से लाल झंडे तथा बैनरों लिए मजदूर ने जुलूस में बारी मैदान आए. अन्यों में इस रैली को बी टी रणदिवे, पी. राममूर्ति, समर मुखर्जी तथा ज्योति बसुने सम्बोधित किया.

(पृष्ठ 21 का शेष)

में हमारे साथियों ने बेमिशाल साहस और दृढ़ता दिखाया है, संघर्ष के दौरान अपनी जानें भी दी. इन शहीदों की कुर्बानियां बेकार हो जाएगी अगर हम अपने संगठन को चौतरफा ढंग से चुस्त-दुरूस्त करने में सफल नहीं रहे. इसके लिए हमें योजनाबद्ध रूप से काम करना होगा. हमने वर्ग दृष्टिकोण के विकास के लिए कारगर कदम नहीं उठाया है. हमारे केन्द्र को और भी शक्तिशाली बनाना होगा. हर उद्योग को कारगर रूपसे मार्गदर्शन के लिए हमने जिस तरह उद्योगवार कार्यविधि पर बल दिया उसी तरह केन्द्रिय कार्यालय में भी यूनियनों द्वारा तमाम तथ्य भेजा जाना चाहिए जिसके आधार पर विश्लेषणात्मक विचार केन्द्र द्वारा किया जा सके.

दूसरी बात यह है कि सीटू की सदस्यता के बारे में बिचार करना होगा. मजदूरों पर सीटू के बढ़ते प्रभाव तथा उन्हें लामबंद कर संघर्षों को आगे बढ़ाने की हमारी क्षमता बढ़ जाने के बावजूद कानपुर सम्मेलन के समय 1981 की कुल सदस्यता 15 लाख थी. पर सरकारी रेकार्ड में तो दस लाख से भी कम दिखाया जा रहा है. इस लिए हमें इस निष्कर्ष पर पहुचना पड़ रहा है कि बहुत सारे सीटू से सम्बद्ध यूनियन या तो वार्षिक विवरण दाखिल नहीं किया या विवरण में सीटू से सम्बद्ध लिखना भूल गया. हमारे राज्य कमेटियों को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप सीटू को ई.पी.एफ. ट्रस्टी बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया जबकि अन्य संगठनों जिनकी कोई क्षमता ही नहीं है, झूठे सदस्यता दिखाकर प्रतिनिधित्व पा लिया. किसी कमेटी में होने या न होने के लिए ही सिर्फ यह मिशाल हम नहीं दे रहे हैं बल्कि हम यह कहना चाहते हैं कि सीटू का किसी सरकारी कमेटी में रहने का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जिसके बदौलत हम मजदूरों के स्वार्थ को आगे बढ़ाने के साथ साथ उस उद्योग या संगठन के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते है.

वर्तमान स्थिति पर हम आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहेगें. प. बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, और कुछ हद तक उड़ीसा में हम देख रहे हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलनों के साथ साथ किसानों के संघर्ष एवं जनवादी आंदोलन भी बढ़ रही है. इस विशेषता का हम स्वागत करते हैं.

हम पहले बता चुके हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, तालाबंदी व क्लोजर के खिलाफ वाम जनवादी तथा विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन करने का फैसला लिया है. इस जनवादी आंदोलन के साथ ट्रेड यूनियन आंदोलन का, भविष्य में मिल जाने की सम्भावना वास्तविक हो रहा है. यह एक दिशा सुचक है और हमें इन संघर्षों में अगुआई के लिए मजदूर वर्ग को तैयार करने का कर्त्तव्य को पूरा करना होगा. हमें विश्वास है कि गहराते आर्थिक संकट तथा राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर बढ़ते अशांत वातावरण के इस पृष्ठ भूमि में जनवादी आंदोलनों का निर्माण की इस महत्वपूर्ण काम को हमारे साथी समझते हैं आइये हम सब मिलकर इस काम को पूरा करें.

(पृष्ठ 31 का शेष)

से मजदूर वर्ग विरोधी साजिश के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें तथा इस बिल को वापस लेने की मांग करें.

लघु उद्योग तथा घरेलू इस्तेमाल के लिए कोयला आपूर्ती पर

जमशेदपुर में 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक रिफैक्ट्रियों, इन्जिनियरिंग तथा सेरामिक फैक्ट्रियों, ईंट-भट्टियों जैसे लघु उद्योग तथा आम लोगों के घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला की आपूर्ती न करने की ई सी एल की नीति पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है. इस जन-विरोधी नीति के कारण कोयले की कीमत तेजी से बढ़कर 50 रु. प्रति मन हो गई है जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है. कोयला की आपूर्ती में कमी के कारण लघु उद्योगों में ले-आफ व क्लोजर हो रहा है और हजारों मजदूर बेरोजगार किए जा रहे हैं.

यह बैठक मांग करती है कि कोयला आपूर्ती के इस जन-विरोधी नीति को पलटकर, जन-वितरण प्रणाली के जरिये आसान शर्तों पर आम लोगों के इस्तेमाल के लिए तथा पर्याप्त मात्रा में लघु उद्योगों के लिए कोयला उपलब्ध कराई जाय जिससे उद्यमकर्त्ताओं तथा मजदूरों को बचाया जा सके.

रानीगंज बंगाल पेपर मिल के क्लोजर पर

जमशेदपुर में, 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 1983 को सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक बी. पी. मिल्स मैनेजमेंट की धांधलियों को गम्भीरतापूर्वक नोट करती है जिसने 1.11 83 को अचानक मिलबन्दी घोषणा करते हुए 3,000 मजदूरों को बेरोजगार बना दिया.

31-12-80 को पिछले समझौते समाप्त होने के बाद बंगाल पेपर मिल मजदूर यूनियन ने 1-1-81 को नये सूत्री मांगों को पेश किया जिसे अमल में न लाकर मालिकों ने कोषों की कमी, उत्पादन में कमी, कच्चे मालों का न मिलने की बातें करने लगे. आखिरकार मजदूरों को संघर्ष के रास्ते पर उतरना पड़ा और पहले एक दिन और फिर दो दिनों की सफल हड़तालें भी हुई. राज्य के श्रम मन्त्री सीटू नेता के.पी. घोष के हस्तक्षेप के बावजूद मालिकान मजदूरों को वेतन तथा बोनस देने से इन्कार किया और उच्चन्यायालय से इसके खिलाफ स्थगन आदेश भी ले लिए.

यह बैठक बी. पी. मिल मैनेजमेंट की इस रुख की भर्त्सना करती है तथा मिल को खोले जाने व यूनियन के साथ वेतन समझौता किए जाने की मांग करती है. यह बैठक संघर्षरत मजदूरों को सम्पूर्ण समर्थन देती है तथा रानीगंज क्षेत्र के मजदूरवर्ग से इस संघर्ष के साथ एकजुटता का इजहार करने का आह्वान करती है.